शुभ धनतेरस

राष्ट्रीय हिंदी दैनिक

लोक शक्ति

धनतेरस आज

RNI Regn. No.7789/1964 वर्ष-61 > अंक - 290 रायपुर शनिवार 18 अक्टूबर 2025 विक्रम संवत 2082 पृष्ठ 8 > मूल्य : 2 रू. डाक पंजीयन : C.G./RYP DN/71/2023-25

छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी सफलता : लाल आतंक का अध्याय अंत की ओर

208 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, एके-47 समेत 153 घातक हथियार डाले

संवाददाता

लोकशक्ति। रायपुर. छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई में शुक्रवार 17 अक्टूबर को सुरक्षा बलों और सरकार को एक ऐतिहासिक सफलता मिली है. दंडकारण्य के घने जंगलों में सक्रिय 208 नक्सलियों ने एक साथ हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया है. इसे राज्य में अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना जा रहा है. इन नक्सलियों ने एके-47 और इंसास राइफलों सहित कुल 153 घातक हथियारों का जखीरा भी जमा कराया है।

इस बड़े आत्मसमर्पण के साथ ही नक्सलियों का गढ़ माना जाने वाला अबूझमाड़ क्षेत्र लगभग पूरी तरह से नक्सल-मुक्त हो गया है और उत्तर बस्तर से 'लाल आतंक' का लगभग सफाया हो गया है. छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार की नक्सल विरोधी नीतियां रंग ला रही हैं. पिछले दो दिनों में कुल 258 नक्सली मुख्यधारा में लौट चुके हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ से 197 और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से 61 नक्सली शामिल हैं. आज सरेंडर करने वालों में कई बड़े कमांडर भी शामिल हैं, जो जंगलों से निकलकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं.

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने न केवल खुद को कानून के हवाले किया, बल्कि अपनी ताकत का प्रतीक रहे आधुनिक और पुराने हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी सुरक्षा बलों को सौंप दिया है. जमा कराए गए कुल 153 हथियारों में 19 खूंखार एके-47 राइफलें, 23 इंसास राइफलें और 17 एसएलआर जैसी घातक ऑटोमेटिक राइफलें शामिल हैं. इसके अलावा, एक एलएमजी (लाइट मशीन गन), 11 बीजीएल लॉन्चर और 4 कार्बाइन भी जमा कराए गए हैं. इस जखीरे में 36 पुरानी .303 राइफलें, 41 बारह-बोर की बंदूकें और एक पिस्टल भी शामिल है. इतने बड़े पैमाने पर इन खतरनाक हथियारों के जमा होने से सुरक्षा बलों को बड़ी राहत मिली है.

इस बड़ी कामयाबी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है. उन्होंने कहा कि अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर अब नक्सल-मुक्त हैं. शाह ने दोहराया कि सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी इस पर खुशी जताते हुए कहा कि यह राज्य में शांति और विकास के एक नए युग की शुरुआत है. उन्होंने कहा कि नक्सलवाद अब हर मोर्चे पर हार रहा है.

अबूझमाड़ का घना जंगली इलाका, जो सालों से नक्सलियों का गढ़ था, अब विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा. यहां अब सड़कें, स्कूल और अस्पताल बन सकेंगे और लोग बिना डर के जीवन जी सकेंगे. सरकार के अनुसार, अब केवल दक्षिण बस्तर के कुछ इलाकों में ही नक्सल समस्या बची है, जिसे जल्द खत्म करने की उम्मीद है. सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर करने वाले इन सभी नक्सलियों को नई जिंदगी शुरू करने में मदद की जाएगी. उन्हें आर्थिक मदद, आजीविका के लिए प्रशिक्षण, परिवार को सुरक्षा और बच्चों को शिक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि वे समाज का हिस्सा बनकर एक सामान्य जीवन जी सकें।

नक्सलियों का सामूहिक सरेंडर ऐतिहासिक : साय

एजेंसी

नक्सलियों के सामूहिक सरेंडर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा- आज का दिन केवल बस्तर ही नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और देश के लिए ऐतिहासिक है। आज बस्तर में 210 नक्सली, जो कभी माओवाद के झूठ में उलझकर वर्षों तक अंधेरी राहों पर भटकते रहे, उन्होंने संविधान और हमारी नीतियों पर विश्वास जताते हुए विकास की मुख्यधारा को अपनाया है। आज उन्होंने अपने कंधों से बंदूक उतारकर, अपने हाथों में संविधान को थामा है। आज बस्तर में बंदूकें छोड़कर सुशासन पर विश्वास जताने वाले इन युवाओं से मुलाकात मेरे जीवन के सबसे भावनात्मक और संतोष देने वाले पलों में से एक है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा- हमारी नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025, नियद नेल्ला नार योजना और पूना मारगेम पुनर्वास से पुनर्जीवन जैसी योजनाएं, विश्वास और परिवर्तन का आह्वान है। इन्हीं नीतियों की ताकत है कि आज नक्सली हमारी सरकार की विश्वास और विकास की प्रतिज्ञा को स्वीकार कर रहे हैं, बंदूक छोड़कर आत्मसमर्पण की राह चुन रहे हैं।

गुजरात : भूपेंद्र पटेल सरकार के नए मंत्रियों ने ली शपथ, रवींद्र जडेजा की पत्नी सहित 25 बने मंत्री

मंत्रियों का कोटा हुआ पूरा

एजेंसी गुजरात विधानसभा में 182 सीटें हैं. नियम के मुताबिक कुल सीटों के 15 प्रतिशत तक मंत्री हो सकते हैं. इस हिसाब से गुजरात में मुख्यमंत्री के साथ 26 मंत्री बनाए जा सकते हैं. इस नई कैबिनेट शपथ ग्रहण से मंत्रियों का कोटा अब पूरा हो गया है. भूपेंद्र सरकार के इस बदलाव में पहली बार विधायक बनी रिवाबा जड़ेजा को भी मंत्रि बनाया गया है. शपथ ग्रहण कार्यक्रम में रवींद्र जडेजा भी शामिल हुए हैं.

हार्दिक पटेल को फिर नहीं मिली जगह - मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के कैबिनेट के इस्तीफे के बाद से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, कि नए विस्तार में हार्दिक पटेल को जगह मिल सकती है. हालांकि इस बार भी उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है. कांग्रेस से बीजेपी में गए हार्दिक पटेल अभी अहमदाबाद की वीरमगाम सीट से विधायक हैं. कुछ समय पहले गुजरात के पाटीदार नेता और पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने एक कार्यक्रम में हार्दिक के मंत्री बनने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन हार्दिक की ये इच्छा इस बार भी अधूरी ही रह गई है।

इन चेहरों को मिली जगह

पुरुषोत्तम सोलंकी । कुंवरजी बावलिया । प्रफुल्ल पानशेरिया ऋषिकेश पटेल । कानू देसाई हर्ष संघवी । अर्जुन मोढवाडिया । नरेश पटेल । कांति अमृतिया । प्रद्युम्न वाज कौशिक वेकारिया । स्वरूपजी ठाकोर । त्रिकम छंगा । जयराम गामित । जीतू वाघाणी । दर्शनाबेन वाघेला । रिवाबा जड़ेजा । पी.सी. बरंडा । रमेश कटारा । ईश्वरसिंह पटेल । मनीषा वकील । प्रवीण माली । प्रद्युम्न वाज । संजयसिंह महीड़ा । कमलेश पटेल ।

आतंक पर बड़ा प्रहार, 34 साल से पाकिस्तान में छिपे हिजबुल सरगना सैयद सलाहुद्दीन भगोड़ा घोषित

एजेंसी। श्रीनगर जम्मू-कश्मीर में आतंक के खिलाफ जारी निर्णायक लड़ाई में सुरक्षाबलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तरी कश्मीर की एक विशेष अदालत ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना मोहम्मद यूसुफशाह उर्फसैयद सलाहुद्दीन को भगोड़ा घोषित कर दिया है। लगभग 34 वर्षों से पाकिस्तान में छिपे सलाहुद्दीन के खिलाफ इस फैसले से पुलिस को उसकी और उसके साथियों की नकेल कसने में और मदद मिलेगी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्रवाई उत्तरी कश्मीर के डंगीवच्छा, सोपोर पुलिस स्टेशन में वर्ष 2012 में दर्ज एक मामले के संबंध में की गई है। उन्होंने बताया कि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जिला बडग़ाम और श्रीनगर में दर्ज मामलों में सलाहुद्दीन को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। पुलिस अधिकारी ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद के समूल नाश तक यह लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा, सलाहुद्दीन के खिलाफ अदालत से यह उद्घोषणा हासिल करना, आतंकियों और उनके सरगनाओं की नकेल कसने के हमारे अभियान का ही एक हिस्सा है।

15 सालों के जंगलराज ने बिहार को बीमारू राज्य बनाया : अमित शाह

संवाददाता

बिहार के तीन दिवसीय यात्रा के क्रम में शुक्रवार की शाम पटना के ज्ञान भवन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भाजपा की ओर से आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान लोगों से संवाद करते हुए शाह ने कहा कि लालू-राबड़ी राज के 1990 से 2005 तक बिहार में जो गड्ढ़े हो गए थे, एनडीए की सरकार ने 20 सालों में उसे भर दिया है। अब इस समतल भूमि पर बहुमंजिली एवं आधुनिक इमारतें बनेंगी। विकसित बिहार बनेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरत है जनता के एक और आशीर्वाद की। आप बुद्धिजीवी लोगों से अपील है कि विधानसभा चुनाव में एक बार फि र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी को मौका दें। साथ ही लोगों को मौका देने के लिए प्रेरित करें। शाह ने आगे कहा, 15 साल के जंगलराज में बिहार 50 साल पीछे चला गया था। पिछड़ापन का गड्ढा इतना गहरा था कि नीतीश सरकार ने 20 साल में, जिसमें पीएम मोदी के साथ 11 साल की डबल इंजन सरकार का भी कार्यकाल सम्मिलित है, इन गड्ढों को भरने का काम किया है। अब 21 से 25 साल विकसित बिहार बनाने का होगा।

उन्होंने कहा कि आजादी के पहले एवं उसके उपरांत बिहार समृद्ध राज्य रहा है। पर, 15 सालों के राजद के जंगलराज ने इसे बीमारू राज्य बना दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले चरण में जंगलराज को खत्म किया। ग्राम पंचायतों और निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। सुशासन लाया। अब वह सुशासन बाबू कहलाते हैं। शाह ने कहा कि वर्ष 2014 में केंद्र में नरेन्द्र मोदी की सरकार बनी, इसके बाद बिहार में बड़ी-बड़ी परियोजनाएं आईं। सड़क, पुल-पुलिया बने। घर-घर बिजली, पेयजल, रसोई गैस पहुंची। राज्य से नक्सलवाद को खत्म किया गया। अब तीसरे चरण में बिहार उद्योग एवं रोजगार युक्त होगा। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं की बुद्धमता विश्व में सबसे समृद्ध है। बिहार में दुनिया को बदलने की शक्ति है।

बेल्जियम की कोर्ट ने मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करने का दिया आदेश, तेज हुई देश लाने की प्रक्रिया

एजेंसी। बेल्जियम में एंटवर्प की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है. भारत के अनुरोध पर बेल्जियम के अधिकारियों की ओर से उसकी गिरफ्तारी को वैध करार दिया है. इस घटनाक्रम से नई दिल्ली में वापस लाने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है. मामले से परिचित अफसरों के अनुसार, चोकसी के पास अभी भी उच्च न्यायालय में इस निर्णय के खिलाफ अपील करने का विकल्प मौजूद है. उन्होंने आगे कहा कि इसका मतलब है कि वह तुरंत नहीं आ सकता, लेकिन पहला और एक बहुत ही अहम चरण पूरा हो चुका है।

कर्नाटक सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए आरएसएस को बना रही निशाना - प्रह्लाद जोशी

नई दिल्ली एजेंसी

केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए राज्य सरकार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रही है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, मंत्री जोशी ने कहा कि राज्य में हालात स्पष्ट रूप से कांग्रेस सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हर स्तर पर सरकार की नाकामियों, विकास में रुकावट और कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह की चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा, इस सब से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने यह साजिश रची है। देखते हैं कर्नाटक की कांग्रेस सरकार आरएसएस के खिलाफ क्या नोटिस जारी करती है। उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। आरएसएस पहले सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर चर्चा करेगा और फिर प्रतिक्रिया पर फैसला करेगा। उसके बाद हम अपना रुख तय करेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य के एक मंत्री ने आरएसएस के बारे में मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था और मुख्यमंत्री ने भी राज्य सचिव को पत्र लिखा था।

उन्होंने कहा, वे तमिलनाडु मॉडल अपनाने की बात कर रहे हैं। आज, कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे को उठाया और कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाया।

विदेश | **भारत से कोई दादागिरी नहीं कर सकता, दुनिया सुनती है हमारी बातः रक्षामंत्री**

स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस एमके1ए ने भरी पहली सफल उड़ान

रक्षा मंत्री बोले- यह ऐतिहासिक पल

नई दिल्ली एजेंसी।

भारत की आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति को आज एक नई बुलंदी मिली जब देश के उन्नत स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस एमके1ए ने आज सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान भरी। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के नासिक स्थित एयरक्राफ्ट मैन्यूफैक्चरिंग डिविजन से इस लड़ाकू विमान ने उड़ान भरकर आसमान में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस ऐतिहासिक पल के गवाह खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बने, जिन्होंने इस उपलब्धि को देश के लिए एक मील का पत्थर बताया।

तेजस की यह पहली उड़ान भारत में अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण की दिशा में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। इस विशेष अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलसीए एमके1ए की तीसरी प्रोडक्शन लाइन का भी उद्घाटन किया, जिससे विमानों के उत्पादन में और तेजी आएगी। इससे पहले गुरुवार को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एचएएल के नए 'मिनी स्मार्ट टाउनशिप' प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए संस्थान की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि एचएएल ने इस प्रोजेक्ट के जरिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट (सतत विकास) में एक मिसाल कायम की है। राजनाथ सिंह ने कहा, जब पूरी दुनिया पर्यावरण बचाने की बात कर रही है, ऐसे में HAL का यह मॉडल दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए एक बेंचमार्क बनेगा। हालांकि, तेजस एमके1ए को भारतीय वायुसेना के बेड़े में कब शामिल किया जाएगा, इसकी आधिकारिक तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। लेकिन, एचएएल के अनुसार, आने वाले चार वर्षों के भीतर भारतीय वायुसेना को 83 तेजस मार्क1ए लड़ाकू विमानों की आपूर्ति कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि अमेरिकी इंजन की आपूर्ति में देरी के कारण इसके निर्माण में कुछ विलंब हुआ है।

मेडागास्कर में तख्तापलट के बाद सेना के हाथ आई कमान, कर्नल बनेंगे राष्ट्रपति

एजेंसी

मेडागास्कर में Gen-जेड के उग्र प्रदर्शन की वजह से तख्तापलट हो गया है। तख्तापलट का नेतृत्व करने वाले सेना के कर्नल को राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। कर्नल माइकल रैंड्रियनिरिना की ओर से हस्ताक्षरित एक बयान के अनुसार, शुक्रवार को उच्च संवैधानिक न्यायालय में आयोजित एक समारोह में उन्हें मेडागास्कर के नेता के रूप में शपथ दिलाई जाएगी।

देश से भागे राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना - मेडागास्कर में Gen-Z आंदोलन की वजह से राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना अपनी जान को खतरा बताकर देश से भाग गए थे। अभी यह पता नहीं है कि वह कहां हैं। मेडागास्कर को अफ्रीकी संघ से निलंबित कर दिया गया है। संघ ने कहा है कि वह इस अधिग्रहण को 'पूरी तरह से अस्वीकार' करता है। कर्नल रैंड्रियनिरिना ने हाल ही में कहा था कि सशस्त्र बल 3 सप्ताह से जारी सरकार विरोधी घातक प्रदर्शनों के बाद नियंत्रण अपने हाथ में ले रहे हैं।

युवाओं ने किया प्रदर्शन

मेडागास्कर में प्रदर्शनों का नेतृत्व असंतुष्ट युवाओं ने किया। इन युवाओं ने सरकारी सेवाओं की विफलताओं, गरीबी और अवसरों की कमी के खिलाफ प्रदर्शन किए और अभिजात वर्ग पर भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी Gen-Z मेडागास्कर' के नाम से लामबंद हुए। इससे पहले नेपाल में भी विरोध प्रदर्शनों के बाद नेताओं को सत्ता से बेदखल किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने की निंदा - मेडागास्कर में बने हालात को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, ''संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने मेडागास्कर में सरकार के असंवैधानिक परिवर्तन की निंदा की है और संवैधानिक व्यवस्था एवं कानून के शासन की वापसी का आह्वान किया है।''

ऐसे शुरू हुए थे प्रदर्शन

एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना को फ्रांस के एक सैन्य विमान से देश से बाहर निकाला गया है। फ्र ांस के विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में कोई बयान नहीं दिया है। मेडागास्कर फ्रांस का उपनिवेश रहा है और राजोइलिना के पास कथित तौर पर फ्रांसीसी नागरिकता है, जिसे लेकर भी लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। सरकार विरोधी प्रदर्शन 25 सितंबर को पानी और बिजली की लगातार कटौती के विरोध में शुरू हुए थे।

लद्दाख हिंसा की जांच के लिए केंद्र का बड़ा फैसला,

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी.एस. चौहान करेंगे न्यायिक आयोग का नेतृत्व

लेह/नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्र सरकार ने लद्दाख में 24 सितंबर को हुई दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा और पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए एक बड़ी घोषणा की है। इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बीएस चौहान को इस मामले की न्यायिक जाँच करने के लिए नियुक्त किया गया है। यह घोषणा लेह में मारे गए, घायल हुए या गिरफ्तार किए गए लोगों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए एक नियोजित विरोध मार्च और ब्लैकआउट से ठीक एक दिन पहले आई है। यह कदम केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख के निवासियों के साथ बातचीत की इच्छा को पुनः स्थापित करने के रूप में देखा जा रहा है। लद्दाख में यह हिंसा ऐसे समय में हुई जब लेह के निवासी लंबे समय से केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। 24 सितंबर को हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाए जाने के बाद चार लोगों की मौत हो गई थी और 70 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद स्थानीय अधिकारियों ने तत्काल कर्फ्यू जैसी पाबंदियाँ लगाई थीं, मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया था, और 70 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था,

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी बायोमैट्रिक पद्धति से होगी

उपार्जन केन्द्रों में ट्रायल रन 3 से 6 नवंबर तक

किसान कर सकेंगे 9 नवंबर से ऑफलाईन एवं ऑनलाईन टोकन के लिए आवेदन

सीमावर्ती जिलों में बनाएं जाएंगे चेक पोस्ट

अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धान खरीदी,प्रक्रिया का प्रशिक्षण

रायपुर। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी बायोमैट्रिक पद्धति से की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए धान उपार्जन केन्द्रों में ऑफलाईन के अलावा मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाईन टोकन जारी किए जाएंगे। सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, प्रबंध संचालक विपणन संघ एवं संचालक खाद्य विभाग के मार्गदर्शन में आज सरगुजा एवं दुर्ग संभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को व्यवस्थित और पारदर्शी ढंग से धान खरीदी सम्पन्न कराने के लिए पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। अलग-अलग संभागों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 17 अक्टूबर तक चलेगी। धान खरीदी का कार्य 15 नवंबर से प्रारंभ होगा। प्रशिक्षण में अधिकारियों ने बताया कि विपणन संघ मुख्यालय स्तर पर इन्टीग्रेटेड कन्ट्रोल एंड कमांड सेन्टर की स्थापना की जाएगी एवं मोबाईल एप्प के माध्यम से विभिन्न प्रकार के एलर्ट आदि भेजे जाएंगे। उपार्जन केन्द्रों में धान के उचित रखरखाव, किसानों की सुविधाओं के संबंध में व्यवस्था किये जाने हेतु उपार्जन केन्द्र प्रभारियों और इससे जुड़े अधिकारियों को प्रशिक्षण में जानकारी दी गई।

उपार्जन केन्द्रों को गतवर्षों में दर्ज प्रकरणों एवं संभावित अनियमितताओं के आधार पर संवेदनशील तथा सामान्य में वर्गीकृत किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा संवेदनशील उपार्जन केन्द्रों में विशेष निगरानी रखी जावेगी। इन केन्द्रों में पृथक से नोडल अधिकारी भी नियुक्त किये जायेगें। जिनके द्वारा समय-समय पर उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा इन्टीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेन्टर से प्राप्त अलर्ट मैसेज के आधार पर उड़नदस्ता द्वारा तत्काल कार्यवाही की जाएगी।

प्रदेश के सीमावर्ती उपार्जन केन्द्रों में पर्याप्त चेक पोस्ट की स्थापना की जा रही है, जिससे अवैध धान के आवक को रोका जा सके। जिलों में धान उपार्जन वर्ष 2025-26 का प्रशिक्षण कार्य 31 अक्टूबर 2025 तक जिला एवं अनुविभाग में पूर्ण करा लिया जावे। गतवर्ष की भाँति इस वर्ष भी बायोमेट्रिक आधारित धान उपार्जन किया जाएगा। वहीं 3 नवंबर से 6 नवंबर के मध्य उपार्जन केन्द्रों में ट्रायल रन का आयोजन होगा एवं 9 नवंबर से टोकन आवेदन किया जा सकेगा। धान खरीदी के लिए सीमांत एवं लघु कृषकों को 02 टोकन एवं दीर्घ कृषकों को अधिकतम 03 टोकन प्रदाय किया जा सकेगा। अतः सभी जिलों को 30 अक्टूबर तक धान उपार्जन से संबंधित सभी तैयारी पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रशिक्षण में अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष समितियों को शार्टेज की मात्रा निरंक करने तथा शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सुचारू रूप से धान उपार्जन पूर्ण करने पर नियमानुसार इन्सेटिव का भी प्रावधान रखा गया है। भारत सरकार द्वारा उपार्जन केन्द्रों के स्वमूल्यांकन हेतु उपलब्ध पोर्टल पीसीएसएपी में उपार्जन केन्द्रों द्वारा धान खरीदी के संबंध मे आवश्यक व्यवस्था पूर्ण कर लेने के उपरांत प्रविष्टि करनी होगी। प्रविष्टि के आधार पर एल-4 ग्रेडिंग पाये जाने पर ही इन्सेटिव की पात्रता उप समिति को होगी। समितियों में डाटा एन्ट्री आपरेटरों का नियोजन 06 माह के लिए समितियों के माध्यम से किये जाने का प्रावधान इस वर्ष की पॉलिसी में किया गया है।

ऐसी समितियां जहां अनियमितताएं पाई गई हो, वहां के डाटा एन्ट्री आपरेटरों का नवीन नियोजन किये जाने के निर्देश दिए गये है।

कोतवाली पुलिस राजनांदगांव की कार्यवाही, एक आरोपी को धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार

आरोपी के कब्जे से 49 पौवा देशी प्लेन मदिरा मात्रा 8.820 बल्क लीटर कीमती 3920 रूपये एवं एक्टीवा मोटर सायकल किमती 20,000 रूपये किया गया जप्त

राजनांदगांव । पुलिस अधीक्षक महोदय राजनादगांव मोहित गर्ग (भा0पु0से0) के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन (भा0पु0से0) राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक नंदकिशोर गौतम के नेतृत्व मे थाना कोतवाली पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों एवं अवैध शराब बिक्री करने वालो के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 14.10.2025 को मुखबीर की सूचना पर घेराबंदी कर घटना स्थल गंज चौक सोनकर कृषि केन्द्र के सामने राजनांदगांव में आरोपी विनित लोन्हारे पिता स्व0 भंवर लाल लोनहारे उम्र 21 वर्ष साकिन राम नगर पॉवर हाउस के पास राजनांदगांव थाना सिटी कोतवाली जिला राजनांदगाव (छ0ग0) को अवैध रूप से बिक्री करने शराब को एक्टीवा मोटर सायकल क्रमांक सी0जी0 08 ए0एम0-5966 से परिवहन कर ले जाते रंगे हाथ पकड़ा गया जिसके कब्जे से 49 पौवा देशी प्लेन शराब 8.820 बल्क लीटर किमती 3,920 रूपये एवं उक्त एक्टीवा वाहन को जप्त कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलॉफ प्रर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने से अप0क्र0 617/25 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के प्रयासों से गन्ना किसानों को दीपावली पर मिला बड़ा तोहफा

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के प्रयासों से गन्ना किसानों को दीपावली पर मिला बड़ा तोहफा

भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना के गन्ना उत्पादक किसानों को 11.09 करोड़ रुपये का बोनस भुगतान

रायपुर। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के सतत प्रयासों एवं किसान हितैषी दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा द्वारा जिले के गन्ना उत्पादक किसानों को दीपावली पर्व के अवसर पर बड़ा आर्थिक लाभ प्रदान किया गया है। कारखाना प्रबंधन द्वारा पिछले पेराई सत्र में गन्ना विक्रय करने वाले किसानों को शासन की ओर से 11.09 करोड़ रुपये का बोनस भुगतान किया गया है। यह बोनस भुगतान उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के विशेष पहल एवं प्रयासों से संभव हुआ है। उनके नेतृत्व में किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध भुगतान और बोनस वितरण सुनिश्चित किया गया है।भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा ने पेराई सत्र 2024-25 के दौरान किसानों से खरीदे गए गन्ने का 115.44 करोड़ रुपये का संपूर्ण भुगतान कर प्रदेश की सभी शुगर मिलों में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि कारखाने की पारदर्शी कार्यप्रणाली, कुशल प्रबंधन एवं सहकारिता की सुदृढ़ भावना का परिचायक है। दीपावली से पूर्व किसानों को बोनस भुगतान प्राप्त होने से पूरे जिले के कृषक समुदाय में हर्ष एवं उत्साह का वातावरण व्याप्त है। बोनस राशि के भुगतान न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाएगी, बल्कि किसानों का विश्वास को और अधिक मजबूत करेगी।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में छत्तीसगढ़ को मिली उपलब्धि पर सीएम ने दी बधाई

रायपुर, । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में मिली छत्तीसगढ़ को उपलब्धि पर बधाई दी है उन्होंने कहा कि यह अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रदेश को 'सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य' घोषित किया गया है। यह सम्मान हमारी सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम है। राज्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों में से 97 प्रतिशत आयुष्मान योजना में सक्रिय हैं, जो देश में सर्वाधिक है और यह योजना के प्रति अस्पतालों के विश्वास का प्रमाण है। हमारी सरकार प्रदेश के प्रत्येक पात्र परिवार को गुणवत्तापूर्ण, निःशुल्क और सम्मानजनक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करने हेतु प्रतिबद्ध है।

नवोदय विद्यालय मॉक टेस्ट परीक्षा शिक्षकों की सामूहिक पहल

अम्बागढ़ चौकी (जिला मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी)। जनजाति विकास एवं उत्थान संस्थान संगठन जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी एवं शिक्षक संकल्प टोली के तत्वावधान में विजन निःशुल्क कोचिंग संस्थान द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय मॉक टेस्ट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षा शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:30 बजे से संस्कार उत्तर माध्यमिक विद्यालय, अम्बागढ़ चौकी में आयोजित होगी। इस मॉक टेस्ट परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के स्तर की तैयारी का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है, जिससे ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्र के विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के प्रति अधिक सजग और आत्मविश्वासी बन सकें। कार्यक्रम का संचालन बी.ई.ओ. श्री एस. के.धीवर एवं बी.आर.सी. श्री संतोष पांडे के मार्गदर्शन में किया जा रहा है।

परीक्षा आयोजन को सफल बनाने में मनहरण पिथौरा,लेकेश्वर ठाकुर, लेख राम ठाकुर, रतन ठाकुर, नीलकंठ कोमरे, दिलीप खरे, मनोज चंद्रवंशी, व्यासु साहू, पुखराज, राजेश्वर साहू, देव यादव, भजन साहू,विजय ठाकुर, रामकुमार, नरेश निषाद, सुभाष कुमार, सहित अम्बागढ़ चौकी के सभी शिक्षकगण सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किसानों के हितों की सुरक्षा हेतु पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुदृढ़ व्यवस्था

प्रदेश के हर अन्नदाता को उसके परिश्रम का पूरा मूल्य मिले, यही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता - मुख्यमंत्री श्री साय

रायपुर, संवाददाता

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की विस्तृत नीति घोषित की है। यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों के हितों और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। खाद्य विभाग की सचिव रीना कंगाले ने जानकारी दी कि धान की खरीदी 3100 प्रति क्विंटल की दर पर की जाएगी। धान उपार्जन का कार्य 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा।

इस वर्ष भी प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। धान खरीदी का सम्पूर्ण कार्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के माध्यम से किया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु चावल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड होगी।धान खरीदी केवल उन्हीं प्राथमिक कृषि साख समितियों और लेम्पस के माध्यम से होगी जो मार्कफेड के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम से जुड़ी होंगी। प्रदेश के सभी जिलों में विगत वर्ष संचालित 2739 खरीदी केन्द्रों और नए स्वीकृत केन्द्रों के माध्यम से खरीदी होगी। इसके साथ ही 55 मंडियों और 78 उपमंडियों का उपयोग धान उपार्जन केन्द्र के रूप में किया जाएगा।

धान खरीदी के लिए आवश्यक साख-सीमा की व्यवस्था मार्कफेड द्वारा राज्य शासन के निर्देशानुसार की जाएगी, ताकि किसानों को समय पर भुगतान में कोई विलंब न हो। प्रदेश में धान उपार्जन प्रक्रिया पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत एवं पारदर्शी होगी। किसान अपने निकटस्थ समितियों में पंजीकरण कर एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से धान विक्रय कर सकेंगे। पोर्टल पर ऋण पुस्तिका आधारित फार्म आईडी से खरीदी की अनुमति दी जाएगी। भारत सरकार कृषि मंत्रालय के एग्रीस्टैक पंजीयन आईडी के आधार पर एकीकृत किसान पंजीयन पोर्टल में कराए पंजीयन फार्मर आईडी से होगा किसान लिंकिंग खरीदी एवं समिति में एग्रीस्टैक पंजीयन होने से समिति में ऋण पुस्तिका लाने की आवश्यकता नहीं होगी। धान खरीदी प्रक्रिया में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को जारी रखा गया है, जिससे पारदर्शिता और वास्तविक किसान की पहचान सुनिश्चित की जा सके। केवल किसान स्वयं, या उनके माता-पिता, पति/पत्नी, या पुत्र/पुत्री ही धान विक्रय कर सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में एसडीएम द्वारा प्रमाणित विश्वसनीय व्यक्ति को अधिकृत किया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से हर घर बन रहा ऊर्जा घर

रायपुर। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से हर घर बन रहा ऊर्जा घरभारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करने हेतु प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना एक क्रांतिकारी पहल सिद्ध हो रही है। यह योजना देश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ एवं सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। योजना के अंतर्गत घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित कर निःशुल्क बिजली प्राप्त की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी, पारदर्शी आवेदन प्रक्रिया तथा सरल तकनीकी व्यवस्था के कारण यह योजना आम नागरिकों के लिए अत्यंत सुलभ बन गई है। इस योजना से न केवल बिजली बिल में बचत हो रही है, बल्कि हरित ऊर्जा के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय कमी आई है।

राज्य में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में यह योजना जनआंदोलन का रूप ले चुकी है। कोरबा जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। जिले के श्री शंकर पुरी एवं श्री टेकराम मरावी जैसे लाभार्थियों ने अपने घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित कर न केवल बिजली बिल को शून्य किया है, बल्कि ऊर्जा उत्पादक बनकर आत्मनिर्भरता की दिशा में उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना अब केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि हर भारतीय की भागीदारी से संचालित हरित क्रांति बन चुकी है।

'हम आत्मनिर्भर हैं और भविष्य को लेकर आश्वस्त भी''हम आत्मनिर्भर हैं आदिवासी स्वरोजगार योजना ने बदली जिंदगी

रायपुर। आदिवासी स्वरोजगार योजना ने बदली जिंदगी, व्यवसाय को मिली मजबूती

छोटी सी मदद कैसे किसी परिवार और उसके भविष्य को सशक्त व आत्मनिर्भर बना देती है, इसकी मिसाल है कांकेर की श्रीमती शारदा उसेंडी। राज्य शासन की पहल से एक छोटे से लोन ने न केवल उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, बल्कि बच्चों की बेहतर पढ़ाई-लिखाई के दरवाजे भी खोले।

बारहवीं तक पढ़ी अंतागढ़ विकासखण्ड के पोण्डगांव की श्रीमती शारदा उसेंडी पहले अपने छोटे से किराना दुकान और थोड़ी-बहुत खेती के सहारे जीवन-यापन कर रही थीं। आय सीमित होने के कारण आर्थिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हो पा रहा था। इसी बीच कांकेर के जिला अंत्यावसायी विभाग के माध्यम से उसे जानकारी मिली कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए ÷आदिवासी स्वरोजगार योजना÷ के तहत ऋण सुविधा उपलब्ध है। उसने तत्परता दिखाते हुए विभाग में आवेदन दिया। विभाग ने उसके आवेदन को भारतीय स्टेट बैंक, अंतागढ़ भेजा, जहां से उसके लिए एक लाख रूपए का ऋण स्वीकृत हुआ। ऋण के साथ ही विभाग की ओर से दस हजार रूपए का अनुदान भी मिला।

श्रीमती उसेंडी ने इस राशि से अपने किराना व्यवसाय को विस्तार दिया। वह बताती है कि अभी उसे दुकान से हर महीने पांच से सात हजार रुपए तक की शुद्ध कमाई हो रही है। उसके पति और बच्चे भी इस व्यवसाय में पूरा सहयोग कर रहे हैं। अपने किराना दुकान की बदौलत उसने नियमित रूप से बैंक की किस्तें चुकाने के साथ-साथ दोनों बेटों की शिक्षा पूरी करवाई है। उसकी बेटी अभी कॉलेज में पढ़ रही है।

श्रीमती शारदा उसेंडी बताती हैं - ÷दुकान के विस्तार के बाद हमारी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई है। अब हम आत्मनिर्भर हैं और भविष्य को लेकर आश्वस्त भी।÷ उसने छत्तीसगढ़ शासन के अंत्यावसायी विभाग, कांकेर के प्रति आभार जताते हुए आदिवासी युवक-युवतियों से अपील की है कि वे ÷आदिवासी स्वरोजगार योजना÷ का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बनने की राह में कदम बढ़ाएं।

सहयोग केंद्र में 200 कार्यकर्ताओं ने दिए आवेदन

16 अक्टूबर को महिला व बाल विकास मंत्री राजवाड़े सहयोग केंद्र में कार्यकर्ताओं से मिलेंगीं

रायपुर,

भारतीय जनता पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने बुधवार को कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएँ सुनीं एवं उनके समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बुधवार को सहयोग केंद्र में 200 से अधिक कार्यकर्ता व आमजन पहुँचे और मंत्री जायसवाल से मुलाकात कर आवेदन दिए। बाद में मंत्री जायसवाल ने कहा कि सभी समस्याओं का तेजी से निराकरण किया जाएगा। प्रदेश की भाजपा सरकार सबके विकास के लिए कार्य कर रही है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी, प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज एवं सहयोग केन्द्र प्रभारी सचिदानंद उपासने सहित पदाधिकारीगण व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। कल गुरुवार 16 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से प्रदेश की महिला-बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सहयोग केंद्र में उपस्थित रहकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई कर उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण करेंगीं।

पीएम नरेन्द्र मोदी के वन स्टेट, वन ग्लोबल डेस्टिनेशन विजन के तहत दिया प्रस्तुतिकरण

चित्रकोट वाटरफॉल को ग्लोबल डेस्टिनेशन में शामिल करने पर बनी सहमति

पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में हुए शामिल

रायपुर। लेकसिटी उदयपुर में पिछले दिनों आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने सम्मिलित होकर राज्य के पर्यटन संभावनाओं और योजनाओं पर केंद्र और अन्य राज्यों के मंत्रियों-अधिकारियों संग विचार-विमर्श किया। श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों को वन स्टेट वन डेस्टिनेशन में शामिल करने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के नियाग्रा कहे जाने वाले चित्रकोट वॉटरफाल को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस संबंध में उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सम्मेलन में राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री विभागीय सचिवों सहित सम्मिलित हुए। इस वर्ष सम्मेलन की थीम 'वन स्टेट-वन ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन' था, जिसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य ने अपने प्रमुख पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने हेतु प्रस्तुतिकरण दिया।

इस अवसर पर केन्द्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र शेखावत ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र का योगदान अब भारत की जीडीपी में लगभग 6 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, जो अगले कुछ वर्षों में 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य आने वाले वर्षों में विश्व के शीर्ष दस पर्यटन देशों में शामिल होना है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2014 में जहां 60 के आसपास थी, वहीं अब यह 39वें स्थान पर पहुंच गई है। यदि केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करें तो अगले पांच वर्षों में भारत इस रैंकिंग को 20वें स्थान तक ला सकता है, और 10 वर्षों में शीर्ष दस देशों में अपना स्थान बना सकता है। इसके लिए केन्द्र सरकार ने 50 ग्लोबल डेस्टिनेशन विकसित करने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि दो दिन के सम्मेलन में बहुमूल्य सुझाव मिले हैं, जो पीएम नरेन्द्र मोदी के वन स्टेट, वन ग्लोबल डेस्टिनेशन के विजन को साकार करने में मील का पत्थर साबित होंगे। पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि वन स्टेट वन डेस्टिनेशन के लिए छत्तीसगढ़ के नियाग्रा कहे जाने वाले चित्रकोट वॉटरफाल व ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के सिरपुर को भी वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हमारी सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहरों और जनजातीय संस्कृति की भव्यता को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में हम कार्यरत हैं। पर्यटन के माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी वहीं पर्यटकों को स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को जानने समझने का बेहतर माध्यम बनेगा। सम्मेलन के दौरान चित्रकोट वाटरफॉल एवं इसके आसपास के प्रमुख स्थलों को भी विकसित करने के लिए कार्ययोजना में जोड़ने की सहमति बनी। वर्ल्डक्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए जो पैरामीटर होनी चाहिए विकसित करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश संबंधितों को दिए गए। छत्तीसगढ़ के पर्यटन विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव ने पीएम नरेन्द्र मोदी के वन स्टेट, वन ग्लोबल डेस्टिनेशन के विजन के तहत छत्तीसगढ़ के धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों के विकास के लिए अपनाई जा रही बेहतरीन योजनाएं साझा की।

सफाई , पेयजल सहित अन्य व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित, अग्निषमन वाहन की व्यवस्था तत्काल करवाने निर्देष

रायपुर – आज नगर पालिक निगम रायपुर की विद्युत एवं अभियांत्रिकी विभाग अध्यक्ष श्रीमती सुमन अषोक पाण्डेय ने नगर निगम जोन 5 जोन कमिष्नर श्री खीर सागर नायक, कार्यपालन अभियंता श्री लाल महेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक राजस्व अधिकारी श्री प्रमोद जाघव सहित नगर निगम जोन 5 के अन्य अधिकारियों, फटाका एसोसिएषन रायपुर के अध्यक्ष श्री असरफहुसैन , सचिव श्री सुनील गुप्ता एवं अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में नगर निगम रायपुर के जोन 5 राजस्व बाजार विभाग द्वारा राजधानी शहर के हिन्द स्पोर्टिंग मैदान लाखे नगर में लगाये जा रहे अस्थायी फटाका बाजार की व्यवस्थाओ का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। एमआईसी सदस्य श्रीमती सुमन अषोक पाण्डेय और जोन 5 जोन कमिष्नर श्री खीर सागर नायक को फटाका एसोसिएषन रायपुर के अध्यक्ष श्री असरफ हुसैन ने सफाई व्यवस्था पेयजल व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओ को लेकर पूर्व वर्षो की अपेक्षा अच्छी व्यवस्था रायपुर नगर निगम से किये जाने की जानकारी दी । उन्होने कहा कि शीघ्र ही अग्निषमन वाहन की भी व्यवस्था अस्थायी फटाका बाजार में उपलब्ध हो जायेगी। इस पर एमआईसी सदस्य एवं जोन 5 जोन कमिष्नर ने तत्काल अग्निषमन वाहन की व्यवस्था अस्थायी फटाका बाजार में सुनिष्चित करने के निर्देष प्रषासनिक व्यवस्था के अनुरूप संबंधित अधिकारियों को दिये। फटाका एसोसिएषन रायपुर के पदाधिकारियों ने रायपुर लाखे नगर हिन्द स्पोर्टिंग मैदान में अस्थायी फटाका बाजार में वाहन पार्किंग व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया है। एसोसिएषन के पदाधिकारियों ने एमआईसी सदस्य और जोन 5 जोन कमिष्नर को बताया कि आवष्यक प्रषासनिक व्यवस्था को लेकर उन्हें कोई षिकायत नहीं है। व्यवस्था संतोषजनक है ।

101 छात्राओं को साइकिल वितरित, शिक्षा की राह हुई आसान

एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप कुमार लाल हुए मुख्य अतिथि के रूप में शामिल

भारतमाला परियोजना में संलग्न कंपनी ने CSR मद से किया वितरण

रायपुरः शिक्षा की पहुँच हर बच्चे तक सुनिश्चित हो, संसाधनों की कमी के कारण कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। समाज तभी सशक्त बन सकता है जब हर बच्चा शिक्षित होकर अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़े। ये बातें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) रायपुर के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप कुमार लाल ने धमतरी जिले के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुरुद में आयोजित साइकिल वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कही।

शुक्रवार को धमतरी जिले के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुरुद की 101 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) रायपुर के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप कुमार लाल ने कहा कि जब एक भी बच्चा अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ता है, तो हमारा विकास अधूरा रह जाता है। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हर बच्चे तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित हो और कोई भी केवल संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित न हो। उन्होंने कहा कि छात्राओं को प्राप्त ये साइकिलें केवल एक साधन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का प्रतीक हैं। इससे निश्चित ही छात्राओं में शिक्षा को लेकर नई प्रेरणा मिलेगी और स्कूल तक की यात्रा आसान होगी।

CSR मद से साइकिल वितरित

भारत सरकार के भारतमाला परियोजना के अंतर्गत निर्माण कार्य में संलग्न मेसर्स शालीमार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कंपनी ने छात्राओं में शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए 101 छात्राओं को साइकिलें वितरित की। इस मौके पर स्कूली विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और लोक नृत्य की शानदार प्रस्तुती दी। इस अवसर पर परियोजना कार्यान्वयन इकाई-अभनपुर के परियोजना निदेशक शमशेर सिंह, प्रखर अग्रवाल शालीमार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रा. लि. के प्रोजेक्ट हेड ब्रजेन्द्र, प्रदीप कुमार सिंह, नागमणि, सुनील कुमार पटेल समेत विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकगण एवं छात्राएँ उपस्थित रहे।

राजधानी के डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड का जनगणना के लिए नगरीय क्षेत्र में प्री टेस्ट जनगणना पूर्व परीक्षण का चयन

सेंट्रिंग प्लेट्स से मिला दी रश्मि के सपनों को सहारा

बिर्रा गांव की रश्मि अब 20 हजार महीने की कमाई से बनी आत्मनिर्भर महिला उद्यमी

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सहित अन्य निर्माण कार्यों में सेंटरिंग प्लेट लगाकर रश्मि के हौसले बुलंद

रायपुर जांजगीर चांपा जिले के जनपद पंचायत बम्हनीडीह के बिर्रा गांव की महिला श्रीमती रश्मि कहरा ने यह साबित कर दिखाया है कि अगर हौसला बुलंद हो और अवसर मिले, तो गांव की मिट्टी से भी सफलता की कहानी लिखी जा सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सहित गांव के अन्य निर्माण कार्यों में सेंटरिंग प्लेट की आपूर्ति कर आज वह हर महीने 20 हजार रुपये की आमदनी अर्जित कर रही हैं। यह सफलता उन्हें बिहान योजना और स्व-सहायता समूह के माध्यम से मिली जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। श्रीमती रश्मि कहरा ने बताया कि पहले परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च दोनों ही मुश्किल में थे। तब उन्होंने हिम्मत जुटाकर रानी लक्ष्मीबाई स्व सहायता समूह से जुड़ने का निर्णय लिया। समूह के सहयोग और बिहान के मार्गदर्शन से उन्हें आत्मनिर्भरता की राह मिली। उन्होंने ग्राम संगठन की सहायता से समुदायिक निवेश कोष से 25 हजार रुपये का ऋण लिया। इस राशि से उन्होंने 1000 वर्गफीट का सेटरिंग प्लेट तैयार कराया, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य निर्माण कार्यों में किराये पर दिया जा रहा है। इसी से आज उनकी नियमित आय 20,000 रुपये मासिक हो गई है। वे कहती हैं पहले जीवन बहुत कठिन था, लेकिन बिहान समूह से जुड़ने के बाद आत्मविश्वास बढ़ा। अब मैं खुद कमा रही हूँ, बच्चों की पढ़ाई कराती हूँ और दूसरों को भी प्रेरित कर रही हूँ। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त किया। गांव की साथी महिलाओं के अनुसार, रश्मि की सफलता से अब कई अन्य महिलाएं भी समूहों से जुड़कर प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य आजीविका गतिविधियों में सक्रिय हो रही हैं। बिहान के जिला अधिकारी का कहना है कि रश्मि की उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि अगर महिला को अवसर, प्रशिक्षण और सहयोग मिले तो वह न केवल अपने परिवार, बल्कि समाज की भी आर्थिक रीढ़ बन सकती है।

महावीर निर्वाण दिवस पर 21 को मांस-मटन विक्रय प्रतिबंधित

रायपुर नगर पालिक निगम रायपुर के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में महावीर निर्वाण दिवस 21 अक्टूबर को मांस-मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

इस संबंध में नगर पालिक निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही ने आदेश जारी किया है। 21 अक्टूबर को नगर पालिक निगम रायपुर के जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण, जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस -मटन के विक्रय पर प्रतिबन्ध के आदेश का पालन करवाएंगे और इसके लिए अपने अपने सम्बंधित जोन क्षेत्रों में मांस मटन की दुकानों का पर्यवेक्षण करेंगे। आदेश का व्यवहारिक पालन करवाने होटलों में उक्त पावन पर्व दिवसों पर मांस-मटन विक्रय करने पर जप्ती की कार्यवाही कर सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही भी की जाएगी।

परिवहन सेवा से बदली महिलाओं की दुनिया

परिवहन सेवा से बदली महिलाओं की दुनिया

फरसपाल की महिलाएं बनी स्वावलंबी की मिसाल

रायपुर, परिवहन सेवा से बदली महिलाओं की दुनिया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में नया उजाला भर दिया है। इस मिशन के माध्यम से गांवों की साधारण गृहणियाँ अब आत्मनिर्भर बनकर समाज में नई पहचान बना रही हैं। ऐसी ही एक प्रेरक कहानी है दंतेवाड़ा जिले के ग्राम पंचायत फरसपाल की महिलाओं की है, जिन्होंने मेहनत, लगन और सरकारी योजनाओं की मदद से स्वावलंबन की मिसाल पेश की है।

स्व सहायता समूह स्थायी आमदनी का मिला साधन ग्राम फरसपाल की गंगादेवी स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने मिलकर एक टाटा मैजिक वाहन खरीदा और आस-पास के गांव आलनार, कुंदेनार, दंतेवाड़ा और गीदम तक परिवहन सेवा शुरू की। इस सेवा से अब ग्रामीणों को आने-जाने में आसानी हो रही है, वहीं महिलाओं को भी स्थायी आमदनी का जरिया मिल गया है। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन की ओर से इन महिलाओं को ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया गया। समूह ने वाहन संचालन के लिए एक ड्राइवर का चयन किया और मिल-जुलकर यह सेवा सफलतापूर्वक शुरू की। आज यह टाटा मैजिक रोजाना सैकड़ों ग्रामीणों की यात्रा का भरोसेमंद साधन बन चुकी है।

महिलाएं अपने परिवार की आमदनी बढ़ा रही हैं समूह की सदस्य श्रीमती यन्ति ठाकुर इस पूरी परिवहन सेवा का हिसाब-किताब और लेखा प्रबंधन देखती हैं। वे बताती हैं कि पहले सिर्फ एक गृहणी थी, जीवन सीमित आय में गुजारती थी, पर जब गंगादेवी स्व-सहायता समूह से जुड़ी, तो बचत और प्रशिक्षण ने उसकी जीवन बदल दिया। अब हम महिलाएं भी अपने परिवार की आमदनी बढ़ा रही हैं।

आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में भागीदार आज समूह की मासिक आय लगभग 26 हजार रुपए तक पहुँच गई है। महिलाओं ने इस कमाई से अपने घरों की आर्थिक स्थिति सुधारी है और बच्चों की शिक्षा, घर की जरूरतों तथा बचत तीनों में संतुलन बना लिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत शुरू हुई यह पहल दिखाती है कि जब महिलाओं को अवसर और सहयोग मिलता है, तो वे न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव की प्रगति में भागीदार बन जाती हैं।

कन्नौजिया क्षत्रिय समाज रायपुर उप समिति ने सर्वसम्मति से निर्वाचन, संपन्न, किशोर सिंह बने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बृज ठाकुर को बनाया

मोतीबाग प्रेस क्लब में समाज के वरिष्ठजनों की उपस्थिति कार्यक्रम संपन्न हुआ

दैनिक लोकशक्ति,रायपुर। रायपुर, 12 अक्टूबर 2025 कन्नौजिया क्षत्रिय समाज रायपुर उप समिति का चुनाव सर्वसम्मति से मोतीबाग प्रेस क्लब में संपन्न हुआ। समाज की इस महत्त्वपूर्ण बैठक में वरिष्ठजनों की उपस्थिति रही और सामाजिक एकता का परिचय देखने को मिला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामबिहारी सिंह परिहार और नवलकिशोर सिंह थे। वहीं केंद्रीय पर्यवेक्षक गजानंद सिंह परिहार और समाज के मार्गदर्शक मनोज सिंह बघेल की उपस्थिति में रायपुर उप समिति की नई कार्यकारिणी का चुनाव किया गया।

निर्वाचित पदाधिकारीः

अध्यक्षः किशोर सिंह
उपाध्यक्षः ब्रिज ठाकुर उर्फगगन
कनिष्ठ उपाध्यक्षः सूरज सिंह परिहार
महिला उपाध्यक्षः रंजना सिंह सोलंकी (पति - श्रीनिवास सिंह सोलंकी)
सचिवः प्रदुमन सिंह भुवाल**महिला सचिवः** नेहा सिंह (पति श्री - प्रकाश सिंह) **सह सचिवः** आयुष सिंह गहरवार**कोषाध्यक्षः** पुष्पेंद्र सिंह परिहार
शहर प्रमुखः अधीर सिंह भुवाल एवं रामधन सिंह

कार्यकारिणी सदस्य

अविभाष सिंह दीक्षित, रामेश्वर सिंह श्रीनेत, अजयपाल सिंह सोलंकी, राकेश सिंह बैस, भूपेंद्र सिंह भुवाल, मनुराज सिंह भुवाल, ब्रजपाल सिंह भुवाल, रामभद्र सिंह बैस, दिलीप सिंह परिहार, प्रकाश सिंह परिहार, हर्ष सिंह बैस, श्रीनिवास सिंह बैस।

समाज के मार्गदर्शक मनोज सिंह बघेल ने नवगठित समिति को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ÷सामाजिक एकता ही समाज के विकास की नींव है। हाल ही में गुरुवाईन डबरी की घटना में समाज की एकजुटता ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई। भविष्य में भी यह एकता बनी रहनी चाहिए।÷ नव निर्वाचित सदस्यों ने यह संकल्प लिया कि रायपुर में कन्नौजिया क्षत्रिय समाज के सामाजिक भवन के लिए सरकारी भूमि आवंटन को प्राथमिक एजेंडा बनाया जाएगा। समिति ने समाज सेवा और सामाजिक उत्थान की दिशा में कार्य करते रहने की प्रतिबद्धता दोहराई।

इस अवसर पर समाज के अनेक गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप सेः

यज्ञ सिंह ठाकुर, सौरभ सिंह परिहार, अनुराग सिंह, कान्हाराज सिंह भुवाल, राणा सिंह, बंशराज सिंह, ऋषिराज सिंह, श्री हरिकपूर सिंह, बल्लभ सिंह राठौर, यश सिंह, योगेश सिंह परिहार, श्रवण सिंह सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित थे।

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

संपादकीय

पाक आतंकियों को पालना करे बंद

आतंकियों की शरणस्थली ना बने पाकिस्तान यह उसकी बेहतरी के लिये उचित होगा। अफगानिस्तान के तालिबान ने जो पाक के खिलाफ युद्ध छेड़ा है इसका नतीजा चाहे जो भी हो यह विश्व में एक नई विचारधार को जन्म दे सकता है। यह महत्त्वपूर्ण है कि अफगानिस्तान संबंधी मास्को फॉर्मेट कंसल्टेशन की बैठक में भारत शामिल हुआ और वहां उभरी एक ऐसी राय से सहमत हुआ, जो स्पष्टतः अमेरिका के खिलाफ है। बैठक में रूस, चीन और पाकिस्तान के प्रतिनिधि भी थे। खबर है कि भारत यात्रा के दौरान अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मोत्ताकी को वह पूरा सम्मान मिलेगा, जो किसी अन्य विदेश मंत्री को प्रोटोकॉल के तहत दिया जाता है। कूटनीतिक हलकों में इसे तालिबान सरकार को भारत की परोक्ष मान्यता के रूप में देखा गया है। इस यात्रा से ठीक पहले हुई एक अन्य घटना से ये राय और मजबूत हुई है।

कविता, संजीव-नी।

मौन क्यूं फैल रहा।

पेड़ों की छाया में,
एक सन्नाटा सा पसरा रहा
पत्तियों की फुसफुसाहट में,
मौन क्यूं पसर रहा है।

नदी के किनारे पर,
एक उदासी और
पानी की आवाज़ में
एक खामोशी गूंजी ।

आकाश के नीचे,
खालीपन सा पसरा रहा
बादलों की ओट में,
नीरव सन्नाटा छाया रहा।

जीवन की राह में भी,
अनिश्चितता सी रही।
कदमों की आवाज़ में,
बेहद खामोशी गूंजी ।

एक सन्नाटा सा पसरा हुआ,
एक खामोशी सी छाई हुई
बरबस इक उदास ,
खालीपन पसरा था।

ना खालीपन् ने ,ना सुनेपन ने
कुछ सोचने की कोशिश की
सन्नाटे का शोर थरथराया रहा
फिर अनकही बातों के बीच
बातें अनंत तलक बंद रहीं।

संजीव ठाकुर

QR CODE SCAN
कर प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़िये ऑनलाईन

PM : 2024 - Vishwa Sarkar Ka Vikalp
Modimaya_ Vaidik_Netritva
Rashtriya Ekta
DLF-Vadra-Bhrasht Tantra
Silent Assassins Jan11,1966
Accursed & Jihadi Neighbour

धनतेरस धन के भौतिक एवं आध्यात्मिक समन्वय का पर्व

ललित गर्ग
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

धनतेरस का पर्व पंच दिवसीय दीपोत्सव की पवित्र श्रृंखला का आरंभिक द्वार है। यह केवल सोना-चांदी, वस्त्र या बर्तन खरीदने का शुभ दिन नहीं, बल्कि धन के प्रति हमारी सोच को पुनर्संतुलित करने का अवसर है। भारतीय संस्कृति में धन को सदैव देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, परंतु यह पूजन केवल भौतिक संपदा का नहीं, बल्कि धन के नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उपयोग का भी प्रतीक है। ऋषि-मुनियों ने धन को केवल मुद्रा नहीं, बल्कि एक ऊर्जा माना है। उपनिषदों में कहा गया है-÷धनं मूलं सर्वेषां साधनानाम्÷, अर्थात धन सभी साधनों का मूल है, परंतु वही धन शुभ है जो धर्म-संयम से अर्जित और लोककल्याण में नियोजित हो। धनतेरस हमें याद दिलाता है कि धन केवल संग्रह का नहीं, उपयोग का विषय है। धन का सही उपयोग ही उसे 'लक्ष्मी' बनाता है, अन्यथा वह 'अलक्ष्मी'-अशांति और विषमता का कारण बन जाता है।

कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। इस तिथि को धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बर्तन, सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। ऐसे में यह दिन धन्वंतरि को समर्पित किया गया है।

भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन कहा गया है। भगवान धन्वंतरि को भगवान विष्णु का अंश माना गया है, जिन्होंने मानव समाज को चिकित्सा विज्ञान (आयुर्वेद) का ज्ञान दिया। इसी कारण धनतेरस के दिन देशभर में वैद्य समाज भगवान धन्वंतरि जयंती के रूप में उनकी पूजा करता है। धनतेरस का ऐतिहासिक महत्व समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा है, जब भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इसे 'धनत्रयोदशी' भी कहते हैं। यह त्योहार भगवान धन्वंतरि को समर्पित है, जिन्हें आयुर्वेद और चिकित्सा का देवता माना जाता है, और धन एवं समृद्धि के देवता भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है। भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी के साथ इस दिन यम दीपक जलाने का भी विधान है। जिसे दीपदान भी कहा जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार, यमराज से अपनी रक्षा करने के लिए इस दिन यमदीपदान किया जाता है। एक कथा के अनुसार, एक राजा के पुत्र को साँप के काटने से मृत्यु होने की भविष्यवाणी थी, जिसे उसकी पत्नी ने दीप और सोने-चाँदी के ढेर लगाकर यमराज को दूर रखने में सफल हुई। जैन आगम में धनतेरस को 'धन्य तेरस' या 'ध्यान तेरस' भी कहते हैं।

प्राचीन भारत में धन का वितरण और उपयोग धर्म और नीति के साथ जुड़ा हुआ था। व्यापारी 'लाभ' में भी 'लोक-लाभ' देखते थे। राजा अपने धन को जनकल्याण, सिंचाई, शिक्षा और सुरक्षा में लगाते थे। किन्तु आधुनिक युग में, विशेषतः पूंजीवादी व्यवस्था के प्रसार के बाद, धन का स्वरूप विकृत हुआ है। धन साधन से लक्ष्य बन गया है। इसके परिणामस्वरूप समाज में अमीरी-गरीबी की खाई, शोषण, और भ्रष्टाचार बढ़ा है। आज एक ओर अरबपतियों की गिनती बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर करोड़ों लोग रोटी और दवा के अभाव में जीवन गुज़ार रहे हैं। धनतेरस का पर्व इस विडंबना पर आत्ममंथन का अवसर है। यह हमें पुकारता है कि हम धन को केवल अपनी तिजोरी का नहीं, बल्कि समाज की समृद्धि का माध्यम बनाएं। लोकमान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन (वस्तु) खरीदने से उसमें तेरह गुणा वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनियाँ के बीज खरीद कर भी घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग-बगीचों में या खेतों में बोते हैं। धनतेरस के दिन चाँदी खरीदने की भी प्रथा है, चांदी शुद्धता की प्रतीक है यहीं शुद्धता इंसानी जीवन में आये, यही इस पर्व का उद्घोष है।

महात्मा गांधी ने कहा था-÷पैसा अपने आप में बुरा नहीं है, परंतु जब वह मनुष्य का स्वामी बन जाता है, तब वह विनाश का कारण बनता है।÷ धनतेरस का सच्चा संदेश यही है-धन का स्वामी बनो, उसका दास नहीं। धन के प्रति सकारात्मक दृष्टि का अर्थ है उसे साधना, सेवा और संस्कार से जोड़ना। आज आवश्यकता है कि हम धन को साझा समृद्धि, सामाजिक उत्तरदायित्व और मानवीय करुणा के उपकरण के रूप में देखें। आज विश्व अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती समान अवसरों का अभाव है। धनतेरस का यह अवसर सरकारों को भी यह संदेश देता है कि वे विकास के लिए धन का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करें। राजकोषीय नीतियाँ केवल अमीर वर्ग के लाभ के लिए नहीं, बल्कि गरीबों के सशक्तिकरण एवं कल्याण के लिए हों। धन की प्रवाह प्रणाली में नैतिकता, पारदर्शिता और संवेदना का समावेश आवश्यक है।

आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने भी धन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। उन्होंने भगवान महावीर के आर्थिक दर्शन को आधुनिक संदर्भों में व्याख्यायित करते हुए 'महावीर का अर्थशास्त्र' नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। आचार्य महाप्रज्ञ ने स्पष्ट किया कि धन का अर्जन और उपयोग दोनों ही अहिंसक, नैतिक और संयमित होने चाहिए। उनके अनुसार धन तभी सार्थक है जब वह आत्मविकास, समाजकल्याण और न्यायपूर्ण व्यवस्था का साधन बने। उन्होंने महावीर के अर्थशास्त्र में बताया कि ÷धन की मर्यादा उसका त्याग नहीं, उसका संयम है।÷ यह विचार धनतेरस के मूल भाव को ही पुष्ट करता है कि धन को नकारा नहीं जाए, बल्कि उसे लोकमंगल में प्रवाहित किया जाए।

धनतेरस का अर्थ केवल भौतिक संपत्ति का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, सदुण और आत्मबल का भी प्रतीक है। आयुर्वेद में इसी दिन धन्वंतरि जयंती भी मनाई जाती है, जो चिकित्सा और स्वास्थ्य के देवता हैं। इस परंपरा में धन का अर्थ केवल पैसा नहीं, बल्कि आरोग्य, अन्न, शिक्षा और शांति भी है। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि धन और धर्म का संवाद पुनः स्थापित हो। धर्म के बिना धन अंधा है, और धन के बिना धर्म असहाय। धनतेरस हमें सिखाता है कि धन का अर्जन सत्य मार्ग से हो और उसका उपभोग सेवा मार्ग पर हो। आचार्य तुलसी ने अर्जन के साथ विसर्जन का सूत्र दिया, यानि अर्जन के साथ जनकल्याण के लिये विसर्जन का क्रम चले। मनुस्मृति में कहा गया है-÷धनं धर्मेण संचिनुयात्÷, अर्थात धन का संचय धर्म के मार्ग से ही किया जाना चाहिए।

धनतेरस केवल सोना-चांदी खरीदने का दिन नहीं, बल्कि धन की शुद्धता और सदुपयोग की तपश्चरण का पर्व है। इस तरह से धनतेरस का पर्व केवल धन प्राप्ति का नहीं बल्कि आरोग्य, आयु और समृद्धि की कामना का पर्व है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि असली संपत्ति हमारा स्वास्थ्य है। इसलिए इस दिन की पूजा न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी है, बल्कि जीवन के संतुलन और सुख-शांति का भी प्रतीक है। आज जब समाज में धन के कारण विभाजन, भ्रष्टाचार और अन्याय बढ़ रहे हैं, तब धनतेरस हमें प्रेरित करता है-धन को 'दिव्यता' में रूपांतरित करने की। यह पर्व हमें पुकारता है कि हम धन के प्रति अपनी दृष्टि बदलें-धन को नकारें नहीं, बल्कि उसे साकार करें; धन से मोह न रखें, परंतु उसे लोकमंगल में प्रवाहित करें। जब धन का प्रवाह धर्म के संग बहता है, तभी सच्चा दीपोत्सव जगमगाता है-अंतर में भी, समाज में भी, और मानवता में भी।

यह निजी विचार है।

इसराइल-हमास संघर्ष शांति, कूटनीति और डोनाल्ड ट्रंप।

संजीव ठाकुर,

लगभग 2 वर्षों के बाद गाजा पट्टी में इसराइल हमास युद्ध अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्तता से थम गया है. इस समझौते में इसराइल के हमास द्वारा बनाए गए इसराइल नागरिक शेष 20 बंधक इसराइल को सौंपें दिए गए बदले में 1900 से ज्यादा बंधकों और फ़िलिस्तीन कैदियों को रिहा किया गयाद्य इस युद्ध में अरबों रूपयों का आर्थिक नुकसान हुआ और गाजा पट्टी फ़िलिस्तीन से एक लाख से ज्यादा नागरिक विस्थापित हुए हैं, और मारे गए इजराइल फ़िलिस्तीन नागरिकों की संख्या बहुत बड़ी है जिसकी सच्चाई का आकलन अभी तक नहीं किया जा पाया है। यह युद्ध विराम मानवता के लिए एक बड़ी राहत संधि मानी जा रही है। इसके बदले डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के ताज में शांति समझौते का एक और नया हीरा जुड़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल पुरस्कार प्राप्ति की आकांक्षा 2026 के लिए फ़िर शुरू हो गई वे अभी भी नोबेल पुरस्कार की दौड़ में बड़े आकांक्षी हैं।

इसराइल-हमास-गाज़ा पट्टी का संघर्ष दशकों से मध्य-पूर्व की राजनीति का सबसे गंभीर अध्याय रहा है। 1948 में इसराइल के गठन के साथ ही अरब-फ़िलिस्तीनी विवाद आरंभ हुआ और 1967 के युद्ध के बाद गाज़ा इसराइली नियंत्रण में आया। 2007 में हमास द्वारा गाज़ा पर नियंत्रण और इसराइल की नाकेबंदी ने तनाव को और गहरा किया। सितंबर 2023 में हमास ने अचानक इसराइल पर हमला कर लगभग 251 नागरिकों को बंधक बना लिया। इस हमले ने न केवल मध्य-पूर्व बल्कि विश्व-राजनीति को भी हिला दिया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने पहले ÷अब्राहम समझौते÷ के माध्यम से अरब-इसराइल संबंधों में शांति का द्वार खोला था, ने इस संकट को अपनी नोबेल शांति पुरस्कार की आकांक्षा से जोड़ते हुए सक्रिय मध्यस्थता की। ट्रंप ने कतर, मिस्र, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय साझेदारों के साथ मिलकर एक बहुपक्षीय शांति प्रारूप तैयार किया। उन्होंने इसे ÷ह्यूमैनिटी फर्स्ट इनिशिएटिव÷ नाम दिया और कहा कि ÷यदि यह समझौता सफल होता है तो मैं नहीं, बल्कि शांति खुद नोबेल की हक़दार होगी।÷ जनवरी 2025 में उनके नेतृत्व में हुए समझौते में 33 इज़राइली बंधकों की रिहाई हुई, जिनमें 25 जीवित और 8 मृत घोषित हुए। इसके बदले इसराइल ने लगभग 1,700 फ़िलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा। यह ÷गाज़ा शांति चरण-1 समझौता÷ कहलाया। इसके बाद अक्टूबर 2025 में शेष 20 जीवित बंधक भी छोड़े गए, जिनकी वापसी को अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने ऐतिहासिक राहत माना। इस रिहाई और युद्धविराम की प्रक्रिया में अमेरिका और कतर के साथ भारत की भूमिका विशेष रूप से रेखांकित रही। भारत ने गाज़ा में मानवीय सहायता, चिकित्सा उपकरण, खाद्य सामग्री और राहत दल भेजे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में दोनों पक्षों से संयम बरतने और आतंकवाद से मुक्त स्थायी शांति की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ÷भारत आतंकवाद के खिलाफहै और निर्दोष जीवन की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा।÷ भारत की यह संतुलित नीति – जहाँ एक ओर इसराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया गया, वहीं फ़िलिस्तीनी नागरिकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया गया,उसे एक विश्वसनीय मध्यस्थ छवि प्रदान करती है। दूसरी ओर, नाटो देशों की प्रतिक्रिया आरंभ में इज़राइल-समर्थक रही। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा ने हमास के हमले को ÷आतंकी कार्रवाई÷ बताया और इज़राइल को सैन्य, तकनीकी और खुफ़िया सहायता दी। परंतु जैसे-जैसे गाज़ा में नागरिक हताहत बढ़े, यूरोपीय संघ और नाटो देशों में मतभेद उभरने लगे। फ्रांस और स्पेन जैसे देशों ने ÷मानवीय संघर्षविराम÷ का आग्रह किया जबकि अमेरिका ने मध्य-पूर्व में स्थायी शांति के लिए कूटनीतिक दबाव बनाए रखा। इस दौरान ट्रंप की व्यक्तिगत भूमिका सबसे निर्णायक बनी रही। उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा कि उनका प्रयास केवल राजनीतिक समाधान नहीं बल्कि ÷मानवता की बहाली÷ है, और उन्होंने इसे अपनी नोबेल शांति पुरस्कार की आकांक्षा से जोड़ा। अंतरराष्ट्रीय समुदाय में उन्हें शांति दूत बनाने का प्रयास किया गया है।

इसराइलङ्कहमासङ्कगाज़ा पट्टी का संघर्ष आधुनिक विश्व की सबसे जटिल मानवीय और राजनीतिक त्रासदियों में से एक है। गाज़ा पट्टी आकार में भले ही छोटी हो, परंतु इसका इतिहास, भू-राजनीति और संघर्ष की गहराई अत्यंत विशाल है। 1948 में इज़राइल राष्ट्र के गठन के साथ ही पहला अरबङ्कइज़राइल युद्ध छिड़ गया था, जिसके बाद गाज़ा मिस्र के नियंत्रण में आया और 1967 के छह दिवसीय युद्ध में इज़राइल ने इस क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया। 1990 के दशक में ओस्लो समझौते के बाद सीमित स्वशासन वाली फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण की स्थापना हुई, किंतु इसके कुछ ही वर्षों बाद हमास नामक संगठन ने धीरे-धीरे राजनीतिक प्रभाव बढ़ाया और 2006 में हुए चुनावों में अप्रत्याशित रूप से विजयी हुआ। 2007 में फ़तह के साथ संघर्ष के बाद हमास ने गाज़ा पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। इसके बाद इज़राइल ने सुरक्षा कारणों से गाज़ा की सीमाओं को सील कर दिया और थल, जल, वायु मार्गों पर कड़ी नाकेबंदी लागू कर दी। इसी के साथ गाज़ा लगातार मानवीय संकट और अस्थिरता का केंद्र बन गया। सितंबर 2023 में विश्व समुदाय तब स्तब्ध रह गया जब हमास ने इज़राइल पर अचानक बड़े पैमाने पर हमला किया। इस हमले में रॉकेट बमबारी, सीमा पार घुसपैठ और नागरिकों पर हमले शामिल थे। हमास के लड़ाकों ने लगभग सात सौ इज़राइली नागरिकों और सैनिकों को बंधक बना लिया और उन्हें गाज़ा में अपनी पकड़ में रखा। यह घटना आधुनिक इज़राइल के इतिहास की सबसे बड़ी सुरक्षा विफलताओं में से एक मानी गई। इसके प्रतिकार में इज़राइल ने ÷ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड÷ नामक भीषण सैन्य अभियान शुरू किया जिसमें गाज़ा पर लगातार हवाई और ज़मीनी हमले किए गए। इस अभियान में हजारों इमारतें ध्वस्त हुईं, सैकड़ों नागरिक मारे गए और लाखों लोग विस्थापित हो गए। मिस्र, कतर और अमेरिका की मध्यस्थता से कई दौर की बातचीत के बाद कुछ बंधकों को मानवीय आधार पर छोड़ा गया, किंतु अधिकांश अब भी लापता हैं। इस युद्ध ने न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस संघर्ष का अंत कहाँ है। गाज़ा में पहले से ही बिजली, पानी, दवाइयाँ और आवास जैसी सुविधाएँ सीमित थीं। अब स्थिति और भयावह हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे 21वीं सदी के सबसे बड़े मानवीय संकटों में एक बताया। अस्पतालों में संसाधनों की कमी, बच्चों और बुजुर्गों की त्रासदी और शरणार्थी शिविरों में बढ़ती भीड़ इस संघर्ष की मानवीय कीमत को दर्शाती है। राजनीतिक दृष्टि से हमास इसे ÷प्रतिरोध का युद्ध÷ कहता है जबकि इज़राइल इसे ÷आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई÷ मानता है। दोनों पक्षों के अपने तर्क हैं, परंतु बीच में पिस रही है आम जनता, जिसकी पीड़ा किसी भी पक्ष के लिए प्राथमिकता नहीं रह गई है। भविष्य को लेकर तीन संभावनाएँ सामने आती हैं। पहली, निकट भविष्य में स्थिति में स्थायित्व नहीं आने वाला है। तब तक वहाँ की हर सुबह धुएँ और आँसुओं में डूबी रहेगी। यही आज की सबसे बड़ी सच्चाई है – कि युद्ध से कोई विजेता नहीं निकलता, केवल पीड़ा और विनाश शेष रह जाता है।

यह निजी विचार है।

सत्य के सच की मीमांसा, सत्य की सार्वभौमिकता सदैव शाश्वत

मनुष्य का समग्र विकास उसकी अदम्य जिज्ञासा, असीम उत्साह, जिजीविषा और निरंतर उन्नति की आकांक्षा का प्रतिफल है। सभ्यता और संस्कृति के विकास-पथ पर मूल्यों का पुनर्संयोजन और परिवर्तन सृष्टि का स्वाभाविक क्रम है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का सनातन नियम है।

विकास के पथ पर धन की भूमिका अवश्य है, परंतु जब धन स्वयं लक्ष्य बन जाए तो वह दिशा को दिग्भ्रमित कर देता है। परिस्थितियों, आवश्यकताओं और युगीन दर्शन के अनुरूप समाज का दृष्टिकोण निरंतर परिवर्तित होता रहता है, किंतु सत्य – वह तत्व है जो समय, देश, समाज, धर्म और संस्कृति से परे, सर्वकालिक और सर्वमान्य बना रहता है।

आदिकाल से ही मानव जीवन में धन और सत्य दोनों की अपनी विशिष्ट भूमिका रही है। धन जीवन की सुविधा का साधन है, जबकि सत्य उसके अस्तित्व का आधार। धन का महत्व है, परंतु धनबल सब कुछ नहीं। सत्य वह दिव्य आलोक है जो अंधकार के पार भी अपनी ज्योति बनाए रखता है।

महात्मा गांधी ने कहा था – ÷सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य।÷

गांधीजी का सम्पूर्ण जीवन इस उद्घोष का साक्षात् रूप था। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सत्य केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन की जीवन्त ऊर्जा है। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं – ÷सत्य में वह शक्ति है जो मानव को असीम बल प्रदान करती है; जो सत्य का पालन करता है, उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती।÷ वेदों और उपनिषदों में भी सत्य को सर्वोच्च मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। ÷सत्यमेव जयते नानृतं÷ – (मुंडक उपनिषद) – यह केवल वाक्य नहीं, भारतीय जीवन-दर्शन का सार है।

भारतीय परंपरा में सत्य को मन, वचन और कर्म की एकता में देखा गया है – 'सांच को आंच नहीं' जैसी लोक कहावतें इसी शाश्वत सत्य की जनभाषा में व्याख्या हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा – ÷तीन बातों को लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकताः सूर्य, चंद्रमा और सत्य।÷

सुकरात ने भी सत्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, पर अपने सिद्धांत से विचलित नहीं हुए।

इमैनुएल कांट ने अपनी नैतिक दार्शनिकता में कहा – ÷सत्य बोलना नैतिक कर्तव्य है, चाहे उसके परिणाम कुछ भी हों।÷ लियो टॉलस्टॉय ने इसे मानवीय आत्मा की सर्वोच्च अवस्था माना – ÷सत्य वही है जो आत्मा को स्वतंत्र करता है।÷ वेदों में कहा गया है – ÷सत्य का सुख स्वर्ण-पात्र से ढका हुआ है।÷

जब धन मुखर होता है, तब सत्य नेपथ्य में चला जाता है। इतिहास साक्षी है कि जब-जब धनबल और सत्ता ने नैतिकता को निगला, तब-तब सभ्यताओं ने पतन देखा है। धन का अतिरेक समाज को नैतिक भ्रम में डाल देता है; भोग और उपभोग की संस्कृति में त्याग, संयम और संतुलन जैसे मूल्य विलुप्त होते जाते हैं।

पश्चिमी औद्योगिक क्रांति के पश्चात धन का प्रभाव वैश्विक स्तर पर इतना बढ़ा कि समाज, राजनीति, धर्म, यहां तक कि शिक्षा और अध्यात्म भी आर्थिक निर्देशों के अधीन होते चले गए। आज धन का नियंत्रण इतना व्यापक है कि राजनीति, न्यायपालिका, मीडिया – सब उसके प्रभाव क्षेत्र में हैं। न्याय भी अब महंगा हो गया है – जैसे विवेक की जगह अब मूल्य (Price) ने ले ली हो। परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि सत्य का दमन कभी स्थायी नहीं होता।

सीमेंट से हथकरघा तक : जीएसटी ने छत्तीसगढ़ में समावेशी विकास को बढ़ावा दिया

पीआईबी

मध्य भारत में स्थित छत्तीसगढ़ का गठन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद किया गया था। यह देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है और यहां 25 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। वनों और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध, यह राज्य अपनी जनजातीय विरासत, सांस्कृतिक जीवंतता और औद्योगिक शक्ति के लिए विख्यात है। इसकी कला और शिल्प परंपराएं- बस्तर के बेल मेटल वर्क और रायगढ़ की बांस कला से लेकर हाथ से बुने हुए कोसा रेशमी कपड़ों तक-कौशल और स्थिरता की एक जीवंत विरासत को दर्शाती हैं।

हाल ही में किए गए जीएसटी सुधारों ने छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी है। आवश्यक वस्तुओं और पारंपरिक क्षेत्रों पर कर की दरों को कम करके, ये सुधार इनपुट लागत को कम करते हैं, उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहित करते हैं और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। हथकरघा, हस्तशिल्प और डेयरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर 5 प्रतिशत जीएसटी दर न केवल छोटे उत्पादकों पर बोझ को कम करती है, बल्कि राज्य की विकासात्मक प्राथमिकताओं और समावेशी विकास विजन के साथ तालमेल बिठाते हुए औपचारीकरण और ग्रामीण उद्यमिता को भी प्रोत्साहित करती है।

सीमेंट उद्योग छत्तीसगढ़ में, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर और नया रायपुर क्षेत्रों में सीमेंट और निर्माण सामग्री उद्योग की मजबूत उपस्थिति है- जहां तेजी से विकास और शहरीकरण हो रहा है। यह उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कर राजस्व के माध्यम से योगदान देता है और सहायक उद्योगों का समर्थन करता है। यह छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नियोक्ताओं में भी शुमार है-

रोजगार में संगठित संयंत्रों (इंजीनियरों, तकनीशियनों, पर्यवेक्षकों) में स्थायी कर्मचारी और खनन, लोडिंग, भट्ठा संचालन, पैकिंग और परिवहन में लगे बड़ी संख्या में संविदात्मक या अकुशल श्रमिक शामिल हैं।

अधिकांश श्रमिक सीमित औपचारिक शिक्षा के साथ ग्रामीण या अर्ध-शहरी पृष्ठभूमि से आते हैं और एक महत्वपूर्ण हिस्सा ओडिशा, झारखंड और उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर हैं।

औसत मजदूरी मामूली है - स्थायी कर्मचारी मासिक रूप से 18,000 रुपये - 35,000 रुपये कमाते हैं, जबकि अनुबंध श्रमिक आमतौर पर 8,000 रुपये -15,000 रुपये कमाते हैं।

महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम बनी हुई है, जो ज्यादातर पैकेजिंग, लोडिंग और संबद्ध सेवाओं तक सीमित है।

संगठित सीमेंट सेक्टर 20,000-30,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।

इसमें 10,000-15,000 की संख्या में अनुबंध मजदूर, ट्रांसपोर्टर और खनिक जैसे अप्रत्यक्ष रोजगार के साथ प्रमुख संयंत्रों में 10,000-15,000 प्रत्यक्ष कर्मचारी शामिल हैं।

सीमेंट क्षेत्र की वृद्धि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से प्रेरित है, जिसमें क्षमता विस्तार के कारण रोजगार में वार्षिक रुप से 5-10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सीमेंट पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने से सीमेंट अधिक किफायती हो गया है, निर्माण लागत कम हुई है, आवास की मांग को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।

हथकरघा और पावरलूम क्षेत्र

हथकरघा उद्योग छत्तीसगढ़ के सबसे प्रमुख कुटीर उद्योगों में से एक है, जो अपने सांस्कृतिक और आर्थिक ताने-बाने में गहराई से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही, राज्य का एमएसएमई और पावरलूम कार्यबल भारत के बड़े वस्त्र इकोसिस्टम की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह देश के सबसे बड़े औद्योगिक योगदानकर्ताओं में से एक है और राष्ट्रीय कपड़ा उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत है।

हथकरघा बुने वस्त्र

छत्तीसगढ़ में, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, रायपुर, महासमुंद, बस्तर और सरगुजा जैसे जिले राज्य के हथकरघा नेटवर्क के गढ़ हैं। हथकरघा बुने हुए कपड़ों में टेरी टॉवलिंग और इसी तरह के बुने हुए टेरी कपड़े शामिल हैं। जांजगीर-चांपा और रायगढ़ के टसर और कोसा रेशम के साथ-साथ रायपुर, दुर्ग, महासमुंद और बस्तर के सूती हथकरघा समूह इस क्षेत्र की कारीगरी उत्कृष्टता को प्रदर्शित करते हैं।

हथकरघा क्षेत्र लगभग 1.5 लाख बुनकरों के लिए एक महत्वपूर्ण आजीविका प्रदान करता है। इनमें से कई महिलाएं हैं, जो विकेंद्रीकृत ग्रामीण उत्पादन में लगी हुई हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत, पिछले आठ वर्षों (2023 तक) में हथकरघा और संबद्ध ग्रामीण उद्योगों में लगभग 8,500 रोजगार सृजित हुए।

इसके अतिरिक्त, 2023 में, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने आर्थिक रूप से निर्बल कारीगरों के लिए कौशल प्रशिक्षण और समूह गठन को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तहत 51 हथकरघा परियोजनाओं को मंजूरी दी।

जीएसटी में 5 प्रतिशत की कमी से इस क्षेत्र को और अधिक ऊर्जा प्राप्त हुई है, जिससे हाथ से बुनी साड़ियां और कोसा/टसर सिल्क के कपड़े अधिक किफायती और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो गए हैं। इससे निर्यात बाजारों में भारतीय हथकरघा उत्पादों को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। इस कदम ने न केवल उपभोक्ता मांग को प्रोत्साहित किया है और बिक्री को बढ़ावा दिया है, बल्कि बुनकरों को सशक्त भी बनाया है। इससे उन्हें छत्तीसगढ़ की बुनाई परंपराओं को बनाए रखते हुए सस्ते, मशीन से बने वस्त्रों के खिलाफप्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिली है और विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोसा/टसर रेशम को लाभ प्राप्त हुआ है।

पावरलूम/मिल आधारित कपड़ा उत्पादन

छत्तीसगढ़ में पावरलूम बुनाई एक अर्ध-संगठित औद्योगिक गतिविधि है, जो रायगढ़, बिलासपुर और जांजगीर-चांपा के आसपास के समूहों में केंद्रित है, जिसमें बलौदाबाजार, महासमुंद , रायपुर, बस्तर और सरगुजा में प्रमुख केंद्र हैं।

श्रीलंका की प्रधानमंत्री का नीति आयोग दौरा

पीआईबी

नीति आयोग ने 16 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉ. हरिनी नीरेका अमरसूर्या की मेजबानी की। यह यात्रा, दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचा, शिक्षा, पर्यटन, कौशल विकास तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्रों में भारत की परिवर्तनकारी पहलों पर विचार साझा करने पर केंद्रित था।

श्रीलंका की प्रधानमंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में थिंक टैंक और समन्वय मंच के रूप में नीति आयोग की भूमिका की सराहना की और दीर्घकालिक नीति निर्माण को जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के साथ जोड़ने की इसकी अद्वितीय क्षमता का उल्लेख किया। नीति आयोग केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के साथ मिलकर कैसे कार्य करता है, विश्लेषण, साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण और नागरिकों से प्राप्त प्रतिक्रिया को प्रभावी शासन से कैसे जोड़ता है, उन्होंने यह भी समझने की कोशिश की। श्रीलंका की सुधार यात्रा का उल्लेख करते हुए उन्होंने ऐसे संस्थानों की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला जो नीतिगत सुसंगतता, साक्ष्य-आधारित निर्णयों और राजनीतिक चक्रों से परे निरंतरता को बढ़ावा देते हैं।

नीति आयोग के सदस्यों की उपस्थिति में आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन के. बेरी द्वारा संचालित चर्चा में देश में चल रही मल्टीमॉडल अवसंरचना नियोजन के लिए पीएम गति शक्ति, समग्र और समावेशी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पर्यटन एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान में सहयोगात्मक अवसर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा डिजिटल शासन सहित अग्रणी प्रौद्योगिकियों का अवलोकन प्रदान किया गया।

कार्यक्रम में व्यापार, निवेश एवं आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते (ईटीसीए) सहित भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों पर प्रस्तुतियां दी गईं। इसके अलावा पीएम गति शक्ति, शिक्षा सुधार, समग्र, समावेशी और प्रौद्योगिकी-संचालित शिक्षण प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान, जन-जन के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विरासत, पर्यावरण और कल्याण पर्यटन में सहयोग तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल नवाचार और शासन में सहयोग पर भी प्रस्तुतियां दी गईं। बैठक में नीति आयोग के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो ज्ञान-साझाकरण और सहयोगात्मक सहभागिता के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस यात्रा ने भारत और श्रीलंका के रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने, सतत विकास को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय चुनौतियों व अवसरों का समाधान करने के लिए नवाचार एवं कौशल का लाभ उठाने के साझा दृष्टिकोण को रेखांकित किया।

समर्पण अनुशासन और समय प्रबंधन से मिलती है सफलता –राज्यपाल श्री रमेन डेका

सीवी रमन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल

195 को पीएचडी एवं 189 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से नवाजा

राज्यपाल ने विद्यार्थियों को दी जीवन मूल्यों की सीख

रायपुर,

राज्यपाल श्री रमेन डेका कोटा स्थित डॉ. सीवी रमन विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने 195 विद्यार्थियों को पीएचडी को उपाधि और 189 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किया। उन्होंने इस दौरान विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित दीक्षांत स्मारिका सहित अन्य प्रकाशनों का विमोचन किया। अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में उन्होंने विद्यार्थियों को समर्पण, अनुशासन और निरंतर परिश्रम को जीवन का मूल मंत्र बताते हुए सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि भाषा ज्ञान का माध्यम है, बाधा नहीं। केवल अंग्रेजी जानने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। भाषा ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम हो सकती है, लेकिन यह बाधा कभी नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा में सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब हम उसमें मन, मस्तिष्क और व्यवहार से जुड़ते हैं। राज्यपाल ने दीक्षांत को सिर्फ एक समापन नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत करार दिया। कार्यक्रम में केन्द्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा, बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला, डॉ. सीव्ही रमन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री संतोष चौबे, कुलपति डॉ. प्रदीप कुमार घोष, कुलसचिव डॉ. अरविन्द कुमार तिवारी, आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रोफेसर राजीव प्रकाश, आइसेक्ट समूह के सचिव डॉ. सिद्धार्थ चतुर्वेदी, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, एसएसपी श्री रजनेश सिंह सहित विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। राज्यपाल श्री डेका ने सफलता के तीन मुख्य स्तंभों दृढ़ता, कड़ी मेहनत और अनुशासन पर जोर देते हुए कहा कि यही वे गुण हैं जो किसी भी व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने माता-पिता और समाज के प्रति आभार प्रकट करने की सीख दी। जितनी भी सफलता आप जीवन में प्राप्त करें, अपने माता-पिता और मूल्यों को कभी न भूलें। समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है अब हमें सोचना है कि हमने समाज को क्या दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को समय का प्रभावी प्रबंधन करने का सुझाव देते हुए कहा कि आपके पास आज समय और स्थान दोनों हैं कि इनका सदुपयोग करें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण का माध्यम होनी चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच आपसी संवाद, विश्वास और प्रेरणा का रिश्ता होना चाहिए। शिक्षा समावेशी होनी चाहिए और सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। अपने संबोधन के समापन में राज्यपाल ने सीवी रमन विश्वविद्यालय को भविष्य में एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान बनने की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने आशा जताई कि यह विश्वविद्यालय आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापित करेगा। इस अवसर पर राज्यपाल श्री रमेन डेका ने एक पेड़ मां के नाम पर पौधा रोपण किया।

केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास एवं राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने अपने उद्बोधन में कहा कि सपनों को हकीकत में बदलने के लिए समर्पण, अनुशासन और समय का सही उपयोग अनिवार्य है। उन्होंने युवाओं से निरंतर सीखते रहने का आह्वान किया।

उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा कि दीक्षांत केवल शिक्षा की पूर्णता नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में आपके सक्रिय शुरूआत का योगदान है। कुलाधिपति श्री संतोष चौबे ने विश्विद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(17कैप्शन13)महाराष्ट्र में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक सुविधा में तीसरी उत्पादन लाइन और दूसरी उत्पादन लाइन के उद्घाटन की झलकियाँ। केंद्रीय रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह इस अवसर पर प्रस्तुति देते हुए।

(17कैप्शन12)केंद्रीय रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह महाराष्ट्र में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक सुविधा में तीसरी उत्पादन लाइन और 40 की दूसरी उत्पादन लाइन के उद्घाटन के दौरान एक समूह तस्वीर में।

बैंकिंग प्वाइंट – एक्सप्रेस बैंकिंग एक्सिसस बैंक ने हिताची पेमेंट सर्विसेज के साथ मिलकर पेश किया देश का पहला डिजिटल

नई पीढ़ी की यह बैंकिंग व्यवस्था सबके लिए बैंकिंग को आसान और सुलभ बनाने की दिशा में एक कदम, जिसकी शुरुआत जल्द ही चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।

लोकशक्ति। संवाददाता

भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक, एक्सिस बैंक ने एक अग्रणी एंड-टू-एंड पेमेंट्स और कॉमर्स सॉल्यूशंस प्रदाता हिताची पेमेंट सर्विसेज के साथ मिलकर ÷एक्सप्रेस बैंकिंग÷ लॉन्च किया है। यह देश का पहला डिजिटल बैंकिंग प्वाइंट है। यह नवाचारी ऑमनी-चैनल समाधान शाखा बैंकिंग में क्रांति लाता है, क्योंकि यह सभी बैंकिंग सेवाओं को एक कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में प्रदान करता है। हिताची पेमेंट सर्विसेज की बैंकिंग तकनीक और पेमेंट सॉल्यूशंस विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए, यह डिजिटल बैंकिंग प्वाइंट पहुंच और सुविधा को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

शाखा बैंकिंग सेवाओं में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त जोड़ते हुए, एक्सप्रेस बैंकिंग एक बंडल्ड, कस्टमाइजेबल समाधान प्रदान करता है, जो डिजिटल लॉबी के कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में जल्दी से लागू किया जा सकता है और इसे सेल्फ-सर्विस और असिस्टेड दोनों मोड में संचालित किया जा सकता

है। ग्राहक अब एक्सप्रेस बैंकिंग में 24×7 जाकर नए बैंक खाते खोल सकते हैं, तत्काल कार्ड ले सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉज़िट बुक कर सकते हैं, लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं और यूटिलिटी बिल का भुगतान कर सकते हैं। इस ऑल-इन-वन समाधान में कार्ड प्रिंटर, चेक जमा करने की सुविधा, पासबुक प्रिंटर और एनएफसी जैसी आधुनिक सुविधाएँ शामिल हैं। प्रमुख सेवाओं को डिजिटल बनाने से तेज़ प्रोसेसिंग संभव होती है और यह एडवांस्ड, मॉड्यूलर, स्केलेबल और भविष्य के लिए तैयार सुविधाएँ प्रदान करता है। पारंपरिक बैंकिंग के भरोसे और सुरक्षा को डिजिटल नवाचार की गति और दक्षता के साथ मिलाते हुए, डिजिटल बैंकिंग प्वाइंट को नवीनतम सुरक्षा फीचर्स और आधुनिक, सहज उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस के साथ तैयार किया गया है, जो ग्राहक अनुभव को पहले से बेहतर बनाता है। इसका कॉम्पैक्ट और लचीला सेटअप न्यूनतम जगह लेता है और इसे शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों या सामुदायिक हब, कॉर्पोरेट पार्क, अस्पताल और विश्वविद्यालय जैसे विशेष स्थानों में जल्दी से स्थापित किया जा सकता है। यह नई पीढ़ी का समाधान डिजिटल-प्रथम सुविधाओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं की पूरी श्रृंखला प्रदान करता है, जिससे तकनीक से परिचित ग्राहकों से लेकर पहली बार बैंकिंग करने वाले सभी लोगों के लिए बैंकिंग को सरल और सबके लिए सुलभ बनाया जा सके। एक्सप्रेस बैंकिंग के लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, एक्सिस बैंक के प्रेसिडेंट और हेड - ब्रांच बैंकिंग, नॉर्थ × ईस्ट और ब्रस्ट बिज़नेस, श्री रेनॉल्ड डिसूज़ा ने कहा, ÷डिजिटल बैंकिंग पॉइंट सिर्फ एक तकनीकी नवाचार नहीं है, बल्कि यह एक्सप्रेस बैंकिंग की एक नई सोच का प्रतीक है। सुरक्षित डिजिटल सेवाओं को सहज रूप से जोड़कर यह कियोस्क देशभर के ग्राहकों को – चाहे वे बड़े शहरों में हों या ग्रामीण इलाकों में – एक स्मार्ट, समान और भरोसेमंद बैंकिंग अनुभव प्रदान करता है। यह पहल बैंकिंग को एक नई पहचान देने, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और अलग-अलग वर्गों की बदलती जरूरतों को फ्यूचर रेडी समाधानों के माध्यम से पूरा करने के प्रति हमारे निरंतर संकल्प को दर्शाती है।÷

हिताची पेमेंट सर्विसेज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर - कैश बिज़नेस श्री सुमिल विकमसे ने आगे कहा, ÷हम भारत के पहले डिजिटल बैंकिंग प्वाइंट को लॉन्च करके रोमांचित हैं, जो बैंकिंग सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह तकनीक-चालित बैंकिंग के नए युग की शुरुआत करेगा और पूरे भारत में सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और डिजिटलाइजेशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जैसे-जैसे हम पारंपरिक और डिजिटल बैंकिंग के बीच की खाई को पाटते हैं, हमें विश्वास है कि डिजिटल बैंकिंग प्वाइंट भारत में सुविधाजनक और सुलभ बैंकिंग अनुभव के लिए नया मंच तैयार करेगा।÷

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठकः कलेक्टर-एसपी ने यातायात व्यवस्था सुधार को लेकर दिए कड़े निर्देश

सड़क सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

लोकशक्ति।

जांजगीर-चांपा / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था की समग्र स्थिति, मादक पदार्थ नियंत्रण, सड़क सुरक्षा, साइबर अपराधों की रोकथाम और प्रशासनिक समन्वय को सुदृढ़ करने जैसे विषयों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए है। जिसके तारतम्य में कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे एवं पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पांडेय ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। बैठक में जिले की यातायात व्यवस्था को बेहतर और सुरक्षित बनाने को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री गोकुल रावटे, अपर कलेक्टर श्री ज्ञानेंद्र सिंह ठाकुर, अपर कलेक्टर श्री आर के तंबोली, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कश्यप, श्री उदयन बेहार, जिला परिवहन अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने जिले में चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स की जानकारी लेते हुए वहां शीघ्र सुधारात्मक कार्य कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों पर सांकेतिक बोर्ड, गति अवरोधक, ट्री रिफ्लेक्टर, प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं तत्काल सुनिश्चित की जाएं। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने हाईवे पर मौजूद गौठानों का चिन्हांकन कर आवारा मवेशियों को नियत स्थानों में रखने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही, जिन स्थानों पर पूर्व में दुर्घटनाएं हो चुकी हैं या जहां दुर्घटनाओं की संभावनाएं अधिक हैं, वहां विशेष सतर्कता बरतते हुए मरम्मत और सुधार कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे करने को कहा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्कूलों में सड़क सुरक्षा की जानकारी देने के लिए और जागरूकता कार्यक्रम के तहत रोड सेफ्टी क्लब बनाया जाएगा। कलेक्टर ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अधिक से अधिक कार्रवाई करने और आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस उपाय अपनाने की बात कही। उन्होंने हाईवे पर स्थित उन ढाबों पर विशेष निगरानी रखने को कहा, जहां ट्रक सड़कों पर खड़े रहते हैं या मादक पदार्थों का सेवन कराया जाता है। ऐसे प्रतिष्ठानों को चिन्हित कर नोटिस जारी करने और उन पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। हाईवे पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए भी निर्देश जारी किए गए। उन्होंने पशु चिकित्सा विभाग को अवारा मवेशियों को सुरक्षित रखने की कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने कहा।

पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पांडेय ने सड़क सुरक्षा को लेकर आम नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए संबंधित विभागों को समन्वय कर रोड सेफ्टी कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय समन्वय से अधिकारी-कर्मचारियों को हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट उपयोग के प्रति जागरूक करने कहा। उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। हेलमेट और बेल्ट उपयोग को लेकर विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जिले में पार्किंग की समस्याओं पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा। उन्होंने सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए।

अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन ने वित्त मंत्री, भारत सरकार को लिखा पत्र .....

जांजगीर चांपा /

श्री अग्रसेन जयंती 2026 पर ?100 का स्मारक सिक्का जारी करने किया अनुरोध.....: राजकुमार मित्तल

अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन की ऐतिहासिक पहल.....

जांजगीर चांपा - अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार मित्तल ने भारत सरकार से विनम्र आग्रह किया है, कि आगामी वर्ष 2026 में अग्र कुल पर्वतक महाराजा श्री अग्रसेन जी की जयंती के पावन अवसर पर 100 मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया जाए। श्री मित्तल ने इस संबंध में भारत की वित्त मंत्री माननीया श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को एक विनम्र मांग पत्र भेज कर सादर अनुरोध किया है कि राष्ट्र निर्माण में महाराजा अग्रसेन जी के अमूल्य योगदान के सम्मानार्थ यह सिक्का जारी कर, देश की सांस्कृतिक विरासत में एक ऐतिहासिक अध्याय जोड़ा जाए।

उन्होंने बताया कि महाराजा अग्रसेन जी केवल अग्रवाल समाज के नहीं, बल्कि सम्पूर्ण भारतीय समाज के आदर्श पुरुष हैं, जिन्होंने ÷एक रूपया, एक ईंट÷ जैसे सिद्धांत से सहकारिता, समानता, उद्यमिता एवं आत्म- निर्भरता का सशक्त संदेश दिया। श्री अग्रसेन जी का जीवन दर्शन आज भी ÷सामाजिक न्याय, आर्थिक नैतिकता एवं सहयोग भाव÷ के आदर्श मूल्यों का प्रतीक है। श्री मित्तल ने कहा कि इस मांग के पूरा होने से न केवल अग्रवाल समाज बल्कि सम्पूर्ण भारतवर्ष में एकता, सहयोग और आत्म- निर्भरता की भावना को नया बल मिलेगा। साथ ही, यह सिक्का आने वाली पीढ़ियों के लिए अग्रसेन जी के आदर्शों का प्रेरणास्रोत बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय

अग्रवाल सम्मेलन ने यह भी प्रस्ताव किया है कि सिक्के के एक ओर महाराजा श्री अग्रसेन जी का चित्र, तथा दूसरी ओर भारत सरकार का राजचिह्न एवं वर्ष 2026 अंकित किया जाए। इस मांग पत्र की प्रतिलिपि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला जी एवं दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को भी प्रेषित की गई है, ताकि राष्ट्रीय भावना से जुड़े इस प्रस्ताव को सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता मिल सके। श्री मित्तल ने देश-विदेश के समस्त अग्रवाल संगठनों, संस्थानों एवं समाज बंधुओं से भी अपील की है कि वे इस ऐतिहासिक मांग के समर्थन में अपनी एकजुटता प्रदर्शित करें, जिससे महाराजा अग्रसेन जी के आदर्शों का प्रकाश पूरे विश्व में फैल सके।

ओमप्रकाश की छत बनी मिनी पावर हाउस, बिजली बिल से मिली राहत

ऊर्जा से आत्मनिर्भरता का मिसाल बना पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना

जांजगीर-चांपा / जांजगीर-चांपा जिले के व्हीआईपी सिटी में रहने वाले श्री ओमप्रकाश गुप्ता ने साबित कर दिया कि जब संकल्प और सही योजना साथ हो, तो बदलाव मुमकिन है। कभी हर महीने 10-12 हजार रुपये का बिजली बिल चुकाने वाले श्री गुप्ता आज प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की बदौलत पूरी तरह से ऊर्जा आत्मनिर्भर बन चुके हैं। उनके घर की छत पर लगा 5 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम अब न सिर्फ उनके घर को रोशन करता है, बल्कि उनके परिवार के आर्थिक बोझ को भी हल्का कर चुका है।

श्री गुप्ता बताते हैं कि पहले हर महीने बिजली बिल का भुगतान करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। उनके बिजली बिल के वजह से घरेलू खर्चों पर भी असर पड़ने लगा। लेकिन जब उन्हें प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत आवेदन करने का निर्णय लिया। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होने के कारण उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। शासकीय पोर्टल और बिजली विभाग की सहायता से कुछ ही समय में उनके घर पर सोलर पैनल स्थापित हो गया। अब उनका घर सौर ऊर्जा से चलता है घर मे सभी घरेलू उपकरण तक सभी कुछ सौर ऊर्जा से संचालित हैं। श्री गुप्ता ने बताया कि अब उन्हें बिजली बिल की कोई चिंता नहीं रहती, बल्कि

कृषि महाविद्यालय के चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम

राजनांदगांव। पंडित शिवकुमार शास्त्री कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र राजनांदगांव में बीते दिनों चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ग्रामीण उद्यमिता जागरूकता विकास योजना एवं कृषि औद्योगिक रेडी एंड ए आई ए कार्यक्रम के अंतर्गत ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम ग्राम धामनसरा में आयोजित हुआ। रेडी कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को ग्रामीण कृषि परिस्थितियों, किसानों की समस्याओं तथा कृषि विस्तार गतिविधियों से अवगत कराना है। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉ. विन्नमता जैन के मार्गदर्शन में हुआ। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि इस योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को किसानों से सीधा जुड़ाव, कृषि तकनीकों की समझ, ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन तथा व्यावहारिक कृषि ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉ. नितिन तुर्रे, डॉ. मनोज चंद्राकर, रेडी कार्यक्रम के अधिकारी डॉ. शिवाजी लिमजे, डॉ. अभय बिसेन, डॉ. द्विवेदी प्रसाद, डॉ. महेंद्र देशमुख, डॉ. पूजा साहू एवं डॉ. डिकेश्वर निषाद उपस्थित रहे। सभी विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को ग्रामीण उद्यमिता, कृषि औद्योगिक विकास एवं रेडी कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम में महाविद्यालय के लगभग 70 छात्र-छात्राओं ने सक्रिय भागीदारी दर्ज की।

त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ अनिल मिश्रा सिटी क्लिनिक डी के मेडिकल जांजगीर में 19 अक्टूबर को रहेंगे उपलब्ध

जांजगीर चांपा / जिला मुख्यालय जांजगीर स्थित सिटी क्लिनिक डी के मेडिकल परिसर जांजगीर में दिनांक 19 अक्टूबर रविवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक त्वचा रोग चिकित्सा एवं परामर्श दिया जाएगा ,इस अवसर पर त्वचा रोग विशेषज्ञ के रूप में डॉ अनिल मिश्रा एम बी बी एस ,एम डी (स्किन एंड वीडी) मरीजों को कील मुंहासों के धब्बे , सौंदर्य परामर्श , बाल संबंधी परामर्श सफेद दाग , सोरायसिस,जटिल चर्म रोग ,मस्से वार्ट्स, केलाइडल ,गोखरू ,नाखूनों का सड़ना चेहरे का दाग झुर्रियां ,यौन गुप्त सेक्स रोग संबंधी रोगों के ईलाज हेतु परामर्श देंगे ,इस अवसर पर संयोजक डॉ हर्षवर्धन सिंह मोबाइल 7898767665 अपना योगदान देंगे ,उपरोक्त सुविधा का लाभ उठाने देवेश कुमार सिंह ने अंचल वासीयों से अपील किया है।

तोरणकट्टा में महालक्ष्मी स्थापना 20 अक्टूबर को

राजनांदगांव। शहर से लगे ग्राम तोरणकट्टा में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 20 अक्टूबर को मां महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापना बड़े धूमधाम से की जाएगी। इस आयोजन का संचालन नवयुवक मित्र मंडल तोरणकट्टा द्वारा किया जा रहा है, जो पिछले छह वर्षों से इस धार्मिक परंपरा को निरंतर निभा रहा है।

आयोजक समिति के सदस्य मुकेश कुमार साहू ने बताया कि मां लक्ष्मी की स्थापना एवं पूजा-अर्चना को लेकर ग्रामीणों में विशेष उत्साह है। समिति के अध्यक्ष हेमंत साहू, मोंटू साहू, भूपेश साहू (मूर्तिकार), भानु साहू, गोल्डी साहू और लिकेश साहू सहित सभी सदस्य आयोजन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इस अवसर पर भव्य सजावट, पूजा-अर्चना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय में सीपीआर जागरूकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा पदों की भर्ती हेतु होगा कौशल परीक्षा का आयोजन

जांजगीर-चांपा /

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न संविदा पदों की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया था। जिसमें से 05 संवर्ग के 48 संविदा पदों की 1:10/1:05 में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की सूची 13 जून 2025 को जारी किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि संविदा पदों के लिये शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय (जीएनएम कालेज) जिला चिकित्सालय परिसर जांजगीर, में कौशल परीक्षा/साक्षात्कार आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के लिए 30 अक्टूबर, एमपीडब्ल्यू (पुरुष) यूएचडब्ल्यूसी (15वां वित्त) के लिए 31 अक्टूबर, परामर्शदाता (एनएचएम) के लिए 06 नवम्बर एवं स्टाफ नर्स (एनबीएसयू/एसएनसीयू) व ए ए न ए म (आरबीएसके/एनयूएचएम) के लिए 07 नवम्बर को प्रातः 09 बजे से 11 तक कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा आयोजित की गई है। जिसे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जांजगीर चांपा के नोटिस बोर्ड में भी चस्पा किया गया है। साथ ही जिले के वेबसाइट https://janjgir-champa.gov.in में अवलोकन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जांजगीर-चांपा से संपर्क किया जा सकता है।

दीयों से नहीं, आत्मनिर्भरता से रोशन हुई मोहला की महिलाओं की दीपावली

पारंपरिक ज्ञान और रचनात्मकता का बखूबी उपयोग कर रही हैं महिलाएं

रायपुर,

छत्तीसगढ़ में शासन के द्वारा सभी के विकास के लिए नीतियों का निर्माण कर समावेशी विकास का प्रयास मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इसमें मानव संसाधन में आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और स्वाभिमानपूर्वक जीवन जीने के लिए हौसला देने की भूमिका दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान निभा रही हैं। इस दीपावली पर ऐसी ही मिशाल मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले की महिलाओं ने उदाहरण प्रस्तुत किया है। जहां ग्रामीण महिलाओं ने बिहान के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा सकती हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर महिला स्व-सहायता समूहों ने दीपावली के पारंपरिक पर्व को अवसर में बदल दिया है। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के जहां ग्राम केवट टोला, मोहला और भोजटोला की निवासी महिलाओं ने सामूहिक प्रयासों के साथ अपने पारंपरिक ज्ञान और रचनात्मकता का उपयोग करते हुए दीपावली के उपयोगी वस्तुओं का उत्पाद कर रही हैं। समूह की महिलाए रंगोली पाउडर, रुई की बाती, लक्ष्मी माता की मिट्टी से बनी मूर्तियाँ, अगरबत्ती, मिट्टी के दीये और मटके साथ ही पारंपरिक साड़ियाँ और मनिहारी सामग्री जैसे उत्पाद अपने ही हाथों से तैयार किए।

फटाका व्यवसायियों की बैठक में दिए गए सुरक्षा संबंधी निर्देश

संवाददाता)।

जांजगीर-चांपा / कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे एवं पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पांडेय के निर्देशन में जिले में फटाका बिक्री के दौरान सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरती है। इसी कड़ी में अपर कलेक्टर श्री आर के तम्बोली , एसडीएम जांजगीर श्री सुब्रत प्रधान, जिला कमांडेंट सुश्री योग्यता साहू , मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा पटाखा व्यवसायियों की संयुक्त बैठक ली गई।

बैठक में अधिकारियों ने सभी व्यवसायियों को निर्धारित दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा । साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

फटाका बाजार क्षेत्र में दो पानी के टैंकर तथा एक दमकल वाहन की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा फायर एंड सेफ्टी टीम द्वारा डेमो प्रदर्शित कर व्यापारियों को सुरक्षा के व्यावहारिक उपायों की जानकारी दी गई। जिला प्रशासन ने सभी व्यवसायियों से अपील की है कि वे सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करें ।

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER
PUBLIC WORKS DEPARTMENT, CIRCLE NO-1 RAIPUR (C.G.)

Tender Notice

Contractors, Registered appropriate class in **Unified Registration System [e- Registration]** invited Online tenders for the following works :-

NIT No./ System Tender No.	Name of Work	Probable amount of contract
1	2	3
224/177701	S/R, MOW & DEPOSITE WORK'S IN MEKAHARA SECTION UNDER CONSTRUCTION SUB DIVISION NO.-02 AT - RAIPUR (C.G.) (2nd Call)	Rs. 50.00 Lakh
250/177702	SPECIAL REPAIR WORK OF VARIOUS ROADS & CULVERT OF SUB DIVISION ABHANPUR (PART -2) (1st Call)	Rs. 170.00 Lakh

NIT No.224 System Tender No.177701 Last date of tender Download Date up to 31.10.2025 Time 17:30 PM & NIT No.250 System Tender No.177702 Last date of tender Download Date up to 06.11.2025 Time 17:30 PM

- Note :- All eligible/interested contractors are mandated to get enrolled on the e Procurement portal (**https://eproc.cgstate.gov.in**) in order to download the tender documents and participate in the subsequent bidding process.

Superintending Engineer
P.W.D. Raipur Circle No-1
Raipur (C.G.)

G- 252604248/3

खास खबर

युवक देवेश सिंह की झूठी शिकायत का खुलासा, पुलिस ने शुरू की जांच

कोरबा)। कोरबा में देवेश सिंह ने 10 अक्टूबर को अपने घर में लूट और ब्लेड से हमला होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके दो दिन बाद 12 अक्टूबर को उसने अपहरण और मारपीट का आरोप भी लगाया। पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू की, लेकिन अब यह सामने आया है कि दोनों शिकायतें झूठी थीं।

पुलिस ने जांच में पाया कि देवेश सिंह ने खुद ब्लेड और चॉकलेट खरीदी थी और दोनों घटनाओं में खुद को चोट पहुंचाकर उन्हें लूट और अपहरण का रूप दिया गया। बताया जा रहा है कि मामला पैसों से जुड़ा था।

कोरबा सीएसपी भूषण एक्का ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और अस्पताल में बयान के आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि घटनाएं वास्तविक नहीं थीं। पुलिस अब देवेश सिंह से पूछताछ कर रही है और झूठी शिकायत दर्ज कराने के आरोप में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की संभावना है।

कोरबा हाईवे पर दर्दनाक हादसा, पिता की मौतय मां-बेटी घायल

कोरबा। कटघोरा-बिलासपुर हाईवे पर मंगलवार को एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और नाबालिग बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना चैतमा चैकी क्षेत्र के सुंदरा नाला के पास शाम लगभग 4 बजे हुई। चैतमा चैकी प्रभारी अफसर खान के अनुसार, मृतक की पहचान उदयपुर जिले के केतमा थाना अंतर्गत उमदेवा चैकी क्षेत्र निवासी सुमन साय अगरिया (45) के रूप में हुई है। वह अपनी पत्नी संगीता अगरिया (42) और 15 वर्षीय बेटी कृष्णा के साथ बाइक (सीजी-15-बीडब्ल्यू-5988) पर अपने रिश्तेदार के यहां से उदयपुर लौट रहे थे।

सुंदरा नाला से गुजरते समय एक तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार तीनों सड़क पर गिर गए। हेलमेट पहनने के बावजूद सुमन साय को सिर में गंभीर चोट लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पत्नी और बेटी भी गंभीर रूप से घायल हुईं। घटना के तुरंत बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल मां-बेटी को तुरंत पाली अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक का शव पोस्टमॉर्टम के लिए मरच्यूरी भेजा।

तेज रफ्तार बाइक ने ली युवक की जान, पुल से टकराकर हुई मौत

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पाली क्षेत्र में सड़क हादसे ने एक युवक की जान ले ली। चैतमा चैकी अंतर्गत युवक अपनी बाइक पर तेज रफ्तार में जा रहा था कि अचानक बाइक अनियंत्रित होकर पुल के पिलर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार मौके पर ही मौत के मुंह में समा गया।

हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों को दी जाएगी सिलेबस सहित ज्ञानवर्धक किताबे

- कलेक्टर ने डीईओ को स्कूल, विद्यार्थियों और किताबो की सूची बनाने के दिए निर्देश
- जिले में राज्योत्सव और धान खरीदी की तैयारियों के संबंध में दिए निर्देश
- पारदर्शिता के साथ सही धान खरीदने के निर्देश
- समय सीमा की बैठक में कलेक्टर की विभागीय कामकाजों की समीक्षा

कोरबा । कलेक्टर अजीत वसंत ने समय सीमा की बैठक लेकर विभागीय कामकाजों की समीक्षा की। उन्होंने लंबित प्रकरणों को शीघ्रता से निराकृत करने के निर्देश दिए। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने जिले में संचालित हाइ और हायर सेकंडरी विद्यालयों में सिलेबस की किताबें सहित प्रतियोगिता परीक्षा और अन्य ज्ञानवर्धक किताबों के सेट वितरण के लिए सूची तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल में पढ़ाई करने वाले बालक और बालिकाओं की सूची तैयार करते हुए उनकी आवश्कताओं को ध्यान रखकर किताबो के सेट तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस मनाने जिले में आवश्यक तैयारी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम सूर्यघर के इंस्टॉलेशन में प्रगति लेन के निर्देश विद्युत विभाग को दिए।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री वसंत ने विभागवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने शासन के निर्देशों के तहत 15 नवम्बर से प्रारंभ होने वाली धान खरीदी की प्रक्रिया के सम्बंध में आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अपर कलेक्टर, एसडीएम को मॉनिटरिंग के निर्देश देते हुए जिले में धान खरीदी बिना किसी गड़बड़ी के पारदर्शिता के साथ करने और शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य अधिकारी को राइस मिलर, समितियों की बैठक लेने और सम्पूर्ण तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने किसानों को धान बेचने के लिए पंजीयन कराने हेतु गाँव में मुनादी कराने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री वसंत ने जिले में निवासरत पीवीटीजी परिवारों के घरों में पीएम सूर्यघर योजना अंतर्गत सोलर सिस्टम लगाने और जनपद सीईओ को सहयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत मातृ वंदना योजना में प्रगति लाने, स्वास्थ्य विभाग को टीबी की जांच बढ़ाकर मरीजो का उपचार करने, स्कूल शिक्षा विभाग को अपार आईडी में पंजीयन बढ़ाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विभिन्न विभागों में बहुत पुराने रिकार्ड को नष्ट करने और कार्यालय में अनावश्यक पुराने सामग्रियों को नहीं रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज से संबंधित अधूरे कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश ई एन्ड एम और लोक निर्माण विभाग को दिए। उन्होंने हरदीबाजार-इमलीछापर, दर्री-बरमपुर सड़क के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने बन्द पड़ी योजनाओं के खाते बन्द करने,वंचित लोगो के आयुष्मान कार्ड पूर्ण करने, आयुर्वेद विभाग को एक सप्ताह के भीतर एक सप्ताह के भीतर आईपीडी की सेवा एक सप्ताह में प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने जनपदों और तहसील में ई ऑफिस से फ़ाइल आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम रनाई और साखो के वन अधिकार पत्र का वितरण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर श्री देवेन्द्र पटेल,श्री मनोज कुमार बंजारे, संयुक्त कलेक्टर श्री कौशल तेंदुलकर, माधुरी सोम, एसडीएम कटघोरा श्री तन्मय खन्ना, कोरबा-श्री सरोज महिलांगे, पोड़ी उपरोड़ा- श्री तुलाराम भारद्वाज, पाली-श्रीमती सीमा पात्रे, जनपद सीईओ श्री क्षितिज गुरभेले आदि उपस्थित थे।

पीएम जनमन आवास दो माह में करे पूर्ण

कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने जनपद अंतर्गत लंबित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन आवास अंतर्गत निर्माणधीन कार्यों को दो माह के भीतर पूर्ण कर नए साल में पीवीटीजी परिवारों को घर की चाबी सौपने और नए आवास में गृह प्रवेश कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत विंडो लेबल तक पूर्ण हो चुके आवास को भी दो माह में पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आवास निर्माण सहित अन्य निर्माण संबंधी कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए।

कटघोरा में राष्ट्रीय सेवकों का पथ संचलन, फूलों की वर्षा से किया स्वागत

कोरबा, संवाददाता । राष्ट्रीय स्वयंसेवकों का विजयदशमी पर्व 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे देश में मनाया जा रहा है विजयदशमी पर्व के अंतर्गत कटघोरा में 12 अक्टूबर को कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनिल डागा एवं अध्यक्षता गोपाल प्रसाद उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता ने कहा है कि स्वयं को राष्ट्र का एक घटक मानकर समाज के बीच संघ कार्य का विस्तार 6 चरण में संघ ने तय किया है, सामाजिक सद्भाव, पर्यावरण संरक्षण, हिन्दू सम्मेलन इत्यादि के माध्यम से संघ कार्य को गति देना है, स्वयं सेवक का गणवेश केवल कपड़ों का रूप नहीं, बल्कि जीवन का दृष्टिकोण और सेवा का संकल्प है। गणवेश पहनना स्वयंसेवक को यह याद दिलाता है कि वह व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक सेवा का प्रतिनिधि है। अनुशासन, एकता और समर्पण का प्रतीकजाति, वर्ग और भाषा से ऊपर राष्ट्र के लिए समर्पण,छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर समाज और देशहित में योगदानसंघ के अनुसार, संघ कार्य साधना का प्रतीक है, जो हर शाखा, हर प्रणाम और हर कदम में जीवंत रहता है। यह स्वयंसेवक को केवल दर्शक नहीं रहने देता, बल्कि उसे राष्ट्र निर्माण का सक्रिय भागीदार बनाता है। संघ ने युवाओं को आह्वान किया है कि एक सामान्य व्यक्ति राष्ट्र के लिए क्या कर सकता है, तो शाखा में आकर ही पता चलता है। सैकड़ो राष्ट्रीय स्वयंसेवकों का पथ संचलन बैंड बाजा के साथ संपन्न हुआ। पथ संचलन के समय जगह जगह फुल से वर्षा किया गया जिसमें संस्कार भारती इकाई कटघोरा,अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भाजपा, श्रेय महिला समूह,अग्रवाल समाज,जायसवाल समाज,ब्राह्मण समाज, शिक्षक वर्ग,व्यापारी वर्ग,स्कूली बच्चे भी शामिल रहे। पथ संचलन को देखने के लिए गली मोहल्ले में सभी जाती वर्ग के लोग बाहर निकल गए। पुलिस की कड़ी व्यवस्था किया गया था। कार्यक्रम में भूपेंद्र वर्मा, अनुराग तिवारी,मनोज नायडू, डॉ गोपाल गोस्वामी, शिवशंकर जायसवाल, डाकेस्वर शुक्ला, सत्यम जायसवाल, मयंक कुमार, किशन केशरवानी,दिलीप शर्मा, रामशंकर पटेल, जे एस मानसर,अशोक राठौर, पी एन योगी,राजकुमार यादव,कन्हैया यादव, देव वैष्णव शिव साहू का अथक सहयोग रहा।

नशे में धुत शिक्षक का वीडियो वायरल, बच्चों और महिला शिक्षिकाओं के सामने की अभद्रता

बिलासपुर, संवाददाता

मस्तूरी विकासखंड के ग्राम सोन स्थित एक प्राइमरी स्कूल से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां पदस्थ शिक्षक विश्वकर्मा प्रसाद कश्यप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कक्षा के अंदर नशे की हालत में अपनी शर्ट उतारकर कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा है। घटना 14 अक्टूबर की बताई जा रही है। आरोप है कि शिक्षक अक्सर शराब पीकर स्कूल आता है और बच्चों के साथ गाली-गलौज व मारपीट करता है। घटना के दिन दोपहर करीब एक बजे वह स्कूल पहुंचा और पहले अन्य शिक्षकों से बदसलूकी की। इसके बाद महिला शिक्षकों और छात्रों के सामने अशोभनीय हरकतें कीं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शिक्षक इस कदर नशे में था कि उसके बोलने की ताकत भी नहीं बची थी। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी और वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसकी इस हरकत से स्कूल का माहौल पूरी तरह बिगड़ गया। इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग भी हरकत में आ गया है। विभागीय अधिकारियों ने वीडियो की सत्यता की जांच कर दोषी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। फिलहाल स्थानीय अभिभावकों और ग्रामीणों में शिक्षक के व्यवहार को लेकर भारी नाराजगी है और वे उसकी तत्काल बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं।

शिक्षा जैसे जिम्मेदार पेशे में इस तरह की लापरवाही न केवल विद्यार्थियों के भविष्य के लिए खतरनाक है, बल्कि पूरे व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है।

सुरक्षा व्यवस्था के साए में सर्वे आज : हरदीबाजार में भारी पुलिस और प्रशासनिक बल की तैनाती

कोरबा-हरदीबाजार । एसईसीएल की दीपका परियोजना खदान से प्रभावित ग्राम हरदी बाजार की जमीनों और उन पर स्थित परिसंपत्तियों का सर्वे के लिए आज 15 अक्टूबर 2025, बुधवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के साए में कार्य करना तय किया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अलाधिकारी इस हेतु पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। हरदी बाजार में 15 अक्टूबर को शांति, सुरक्षा और व्यवस्था के मध्य सर्वे कार्य कराया जाएगा किंतु इस दौरान किसी भी तरह की निर्मित होने वाली अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कार्यपालिक दंडाधिकारियों की ड्यूटी लगाने के साथ-साथ जिला पुलिस और सशस्त्र बल के जवानों की भी तैनाती कर दी गई है। **इन अधिकारियों की लगी ड्यूटी,अतिरिक्त कलेक्टर मनोज बंजारे सम्पूर्ण प्रभारी** सर्वे कार्य के दौरान कलेक्टर के आदेशानुसार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिन कार्यपालिका दण्डाधिकारियों की छुट्टी लगाई गई है उनमें सीमा पात्रे एसडीएम पाली, रोहित सिंह, डिप्टी कलेक्टर, अमित केरकेट्टा, तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी दीपका,अभिजीत राजभानू, तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी बरपाली, प्रियंका चन्द्रा, तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी कटघोरा, विष्णु प्रसाद पैकरा, तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी हरदीबाजार, सुश्री राशिका अग्रवाल, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी पाली, संदीप गुप्ता, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक हरदी बाजार शामिल हैं।

कोरबा में सड़कों की दुर्दशा पर 16 को विशाल धरना, 24 से गड्ढा नामकरण अभियान

कोरबा संवाददाता।

शहर के प्रवेश मार्गो गौमाता चैक, ईमलीछापर चैक, कटघोरा रोड की बदहाली तथा शहर के भीतर सड़कों की दुर्दशा में सुधार नहीं होने पर जिला प्रशासन और नगर प्रशासन के खिलाफ 16 अक्टूबर को विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। एक सप्ताह पूर्व जिला कलेक्टर एवं निगम आयुक्त को पत्र देकर सड़कों की दुर्दशा को सुधारने का निवेदन किया गया था। एक सप्ताह से ज्यादा बीत जाने के बाद भी सड़कों का मरम्मत नहीं किया गया। आम जनता की ओर से दिए गए आवेदन पत्र पर प्रशासन ने कोई सकारात्मक पहल भी नहीं की, इसके विरोध में कोरबा की आम जनता और संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। कोरबा के जागरूक नेताओं और संगठनों के

साथ मिलकर 16 अक्टूबर को ट्रांसपोर्ट नगर चैक में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिला प्रशासन एवं नगर प्रशासन के खोखले दावे को सामने लाने के लिए और उनकी आंखें खोलने के लिए 24 अक्टूबर से गड्ढा नामकरण अभियान भी चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत शहर भर के जितने भी जर्जर सड़क एवं गड्ढे हैं वहां जाकर दोषी अधिकारियों के सदबुद्धि के लिए पूजन कर नामकरण किया जाएगा।

सड़कों की दुर्दशा पर प्रशासन के विभाग पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, एसईसीएल, एक दूसरे को जिम्मेदार बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। इसलिए आम नागरिकों के साथ मिलकर गड्ढा नामकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य जर्जर सड़कों के लिए दोषी लोगों की पहचान करना है जिनके आंख मूंदकर सोने के कारण कोरबा की जनता सड़कों को दुर्दशा से प्रताड़ित हो रही है। सत्ता पक्ष के अधिकांश पार्षद अधिकारियों के मनमर्जी और उपेक्षा से दुखी हैं, लेकिन संगठन के दबाव में खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं।

नगर निगम सभापति नूतनसिंह ठाकुर ने कहा है कि नागरिकों के मूलभूत सुविधा सडक, बिजली, पानी के लिए जनता लगातार परेशान हैं। जब निर्वाचित पार्षद अधिकारियों को समस्या बता रहे हैं तो उनकी उपेक्षा हो रही है। अधिकारी कागजी खानापूर्ति कर सरकार को गुमराह कर रहे हैं। त्यौहारी सीजन में आम आदमी सड़कों की दुर्दशा से हलाकान हो रहा है। सड़कों के धूल, गड्ढे के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आम जनता सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पीड़ा बता रही है लेकिन जिला प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। अब सरकार को नींद से जगाने के लिए आंदोलन करना जरूरी हो गया है। धरना प्रदर्शन और गड्ढा नामकरण अभियान के बाद भी सड़कों की बदहाली दूर नहीं हुआ तो चक्काजाम और अनशन किया जाएगा।

कोरबा : पटाखा दुकानों में आग से बचाव हेतु एडवाईजरी जारी

संवाददाता। कोरबा

दीपावली पर्व पर संचालित होने वाले स्थाई व अस्थाई पटाखा दुकानो में आग से बचाव के लिए नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं तथा एस.डी.आर.एफ रायपुर से एडवाईजरी जारी किया गया है। जारी एडवाईजरी में साफ कहा गया है कि पटाखा दुकानो का निर्माण बांस बल्ली और कपडे के बजाय टीन (शेड) के रूप में किया जाएं, इसके अलावा दुकानों पर 5 किग्रा क्षमता का डी.सी.पी अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहे, जांच के दौरान जारी एडवाईजरी का पालन नही करने पर छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

पटाखा दुकानो में किसी भी ज्वलशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादी का ना हो कर अज्वलनशील सामग्री से बने टीन शेड द्वारा निर्मीत होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दुसरे से कम से कम तीन मीटर की दुरी पर एवं एक दुसरे के सामने न बनाई जाए। पटाखा दुकानो में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैंप एवं खुली बिजली बत्ती का उपयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होनी चाहिए। विद्युत तारों में ज्वाईंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्वीच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए जिससे सार्ट शर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बंद हो जाए। दुकाने ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके उपर से हाई टेशंन पावर लाईन न गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में 6 फीट की मारक क्षमता वाली 5 किग्रा का डी.सी.पी अग्नि शामक यंत्र होना चाहिए। दुकानो के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियो के साथ होनी चाहिए। पटाखा दुकानो के सामने बाईक या कार की पार्किंग प्रतिबंधित होना चाहिए। अग्नि शमन विभाग एवं एम्बूलेंस का फोन नम्बर दुकान परिसर के कुछ स्थानो मे लगाया जाए। अग्निशमन मुव्हमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।

आम जनता लाईसेंस प्राप्त विक्रेताओ से ही पटाखे खरीदें, यह सुनिश्चित करें आप गुणवत्ता वाले पटाखे खरीद रहें है, जो दुर्घटनाओ के जोखिम को कम करने के लिए अनुमोदित हो। इमारतो, वाहनो और ज्वलनशील पदार्थो से दूर पार्क बडे मैदान जैसे खुले मैदान में पटाखे जलाऐ। पटाखे जलाते समय संभावित आपातकालीन स्थिति के लिए पानी की बाल्टी निकट रखे। आग से संबंधित चोटो के जोखिम को कम करने के लिए सूती वस्त्र पहनने के लिए प्राथमिकता दे, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े आसानी से आग पकड़ सकते है। एक बार में एक ही पटाखा जलाए, आग लगने की आशंका को देखते हुए एक सांथ कई पटाखे जलाने से बचे। घर के अंदर खिडकियो के पास या अन्य बंद स्थानो पर कभी पटाखे न जलाऐ।

पटाखे जलाते समय ढ़ीले या लटकने वाले वस्त्र पहनने से बचे क्योंकि वे आसानी से आग पकड़ सकते है। ज्वलशील पदार्थो के पास पटाखों का उपयोग न करें, पटाखो को सुखी पत्तियो गैर सिलेण्डर या वाहनो जैसी वस्तुओ से दूर रखें। यदि कोई पटाखा जलने में विफल रहता है तो उसे पुनः जलाने का प्रयास न करें अपितु कुछ देर प्रतिक्षा करने के उपरांत उसका सुरक्षित निपटान करें। किसी भी तरह की चोट लगने या जलने पर तुरंत चिकित्सक की सलाह ले तथा उचित मार्गदर्शन के बिना घरेलु उपचार न करे।

(कोरबा) जिले में दीपावली पर्व से पहले खाद्य विभाग हुआ सतर्क

कई दुकानों से लिए गए सैंपल

कोरबा । जिले में आगामी दीपावली त्यौहार के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कुछ दुकानों से जांच के लिए खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। इनमें पानी, टोस्ट, आटा, सोयाबीन तेल, मैंगो कैंडी, बिस्कुट, कुकीज, पनीर, बूंदी और कलाकंद जैसे उत्पाद शामिल हैं। जानकारी के अनुसार इस दौरान कई दुकानों में गंदगी और अव्यवस्थाएं पाई गईं, जिसके लिए दुकानदारों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। पिछले एक सप्ताह में जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर स्थित रंजय कैंटीन से पानी, जमनीपाली के संजय जनरल स्टोर से टोस्ट और आटा, शिवम जनरल स्टोर से सोयाबीन तेल के नमूने लिए गए।

इसी कड़ी में इतवारी बाजार में संचालित शांति ट्रेडर्स से मैंगो कैंडी और टोस्ट, किशन ट्रेडर्स से बिस्कुट और कुकीज के सैंपल लिए गए। बांकीमोगरा स्थित बुलबुल सेल्स से पानी, राजू होटल से चिकन बिरयानी और वेज बिरयानी, उरगा स्थित सुनीता डेयरी से पनीर, तथा शुभम डेयरी से बूंदी और कलाकंद के नमूने भी जांच के लिए भेजे गए हैं।

विभाग ने सभी प्रतिष्ठानों को त्यौहारी सीजन के मद्देनजर ैाप् नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। उक्त कार्यवाही के दौरान कई होटलों में डस्टबिन नहीं पाए गए, जिसके लिए उन्हें डस्टबिन रखने और गीले व सूखे कचरे को अलग-अलग रखने के निर्देश दिए गए।

गांधी उद्यान से एक्सप्रेस-वे तक बनेगा रायपुर का पहला 6 लेन फ्लाईओवर, बचेंगे 10 मिनट

रायपुर । रायपुर वासियों को बहुत जल्द ट्रैफिक्र से बड़ी राहत मिलने वाली है. रायपुर के गांधी उद्यान से लेकर तेलीबांधा चौक तक एक्सप्रेस-वे को जोड़ने वाले सिक्स लेन का निर्माण किया जाना है. इस सिक?स लेन फ्लाईओवर को करीब 180 करोड़ की लागत से बनाया जाना है. इस सिक्स लेन फ्लाईओवर में 3 लाइन आने और 3 जाने वालों के? लिए बनाई जाएगी. इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने ड्राइंग डिजाइन भी बना ली है. शासन को भेजी गई ड्राइंग डिजाइन लोक निर्माण विभाग ने सिक्स लेन फ्लाईओवर का ड्राइंग डिजाइन शासन को अप्रूवल के लिए भेजा है. शासन से मंजूरी मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. पीडब्ल्यूडी के अफसरों के अनुसार, फ्लाईओवर के लिए तैयारी पूरी हो गई है. शासन की तरफसे हरी झंडी मिलते ही आगे की प्रक्रिया शुरु हो जाएगी. ये फ्लाईओवर राजधानी का पहला सिक्स लेन फ्लाईओवर होगा. फ्लाईओवर का फायदा क्या? बता दें कि, भगत सिंह चौक से तेलीबांधा चौक तक सुबह 8 से रात 11 बजे तक रोजाना करीब 80 हजार से अधिक छोटी-बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं. इसमें मुख्य तौर पर नवा रायपुर, एयरपोर्ट और आरंग जाने वाली गाड़ियां शामिल हैं. गाड़ियों की बड़ी संख्या के कारण पूरे समय इस रोड पर ट्रैफिक्र का प्रेशर रहता है. फ्लाईओवर के बनने से ट्रैफिक्र से राहत मिलेगी. वर्तमान में भगत सिंह चौक से एक्सप्रेस-वे तक करीब 300 मीटर की दूरी में तीन सिग्नल हैं. भारी ट्रैफिक्र के कराण इन सिग्नल पर यात्रियों भारी जत था इकट्ठा हो जाता है. वहीं फ्लाओवर के बनने से ट्रैफिक्र से राहत मिलेगी. तीन साल पहले मिली थी मंजूरी शासन ने इस फ्लाईओवर को तीन साल पहले बजट में मंजूरी दे दी थी. जिसके लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने एक साल पहले इसका स्वाइल टेस्टिंग कराकर फाइल मुख्यालय को भेजी थी>

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर तैयारियां शुरू

रायपुर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। 01 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री मोदी नया रायपुर अटल नगर में राज्योत्सव स्थल में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा वे शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्मित भवन और प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग सेंटर एकेडमी फार ए पीसफुल वर्ल्ड शांति शिखर का शुभारंभ और सत्य सांई हॉस्पिटल में हृदय का ऑपरेशन कराने वाले बच्चों से चर्चा करेंगे। अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ ने आज नवा रायपुर स्थित राज्योत्सव स्थल में प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। श्री पिंगुआ ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी 31 अक्टूबर की रात्रि राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और अगले दिन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान नए विधानसभा भवन के लोकार्पण और राज्योत्सव के शुभारंभ अवसर पर सभाएं होंगी। इन आयोजनों के लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी जाए। बैठक में कलेक्टर गौरव सिंह ने प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर की जा रही तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के सचिव डॉ. एस. भारती दासन, कमिश्नर रायपुर महादेव कावरे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ. लाल उमेंद सिंह सहित जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

अम्बेडकर अस्पताल में दुर्लभ एवं अपने आप में अनोखी सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेग्नेंसी का सफल ऑपरेशन

रायपुर। निःस्वार्थ सेवा, जीवन बचाने की चिकित्सा क्षमता और मानवीय करुणा के कारण डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। कई बार रोगी की जान बचाने के लिए अपने अधिकतम प्रयास की सीमा से ऊपर उठकर वे रोगी को मौत के मुँह से भी निकालकर ले आते हैं। कुछ ऐसे ही सेवा, समर्पण और करुणा की परिभाषा और मिसाल कायम करते हुए चिकित्सालय के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की डॉक्टरों ने न केवल महिला का जीवन सुरक्षित किया बल्कि महिला के जटिलताओं से भरे गर्भ को बचाते हुए उसे मातृत्व सुख का अहसास भी दिलाया।

पं. नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल रायपुर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की टीम ने अत्यंत दुर्लभ और जटिल परिस्थिति में 40 वर्षीय एक गर्भवती महिला की सफल डिलीवरी कर माँ और शिशु दोनों को जीवनदान दिया।

यह मामला सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेग्नेंसी का है, जिसमें भ्रूण गर्भाशय में न होकर पेट (एब्डोमिनल कैविटी) में विकसित हो रहा था। डॉक्टरों के अनुसार यह मध्य भारत का पहला और दुनिया के अत्यंत दुर्लभ मामलों में से एक है।

कई जटिलताएँ और सफल उपचार,दो बार मिला जीवन दान

इस गर्भावस्था के दौरान महिला इमर्जेंसी में चौथे महीने के मध्यरात्रि में अम्बेडकर अस्पताल रेफर होकर आई। स्त्री रोग विभाग ने गंभीरता समझ तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क किया और तुरंत एंजियोप्लास्टी हुई। अम्बेडकर अस्पताल के एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में हुई इस प्रक्रिया में डॉक्टरों ने विशेष सावधानी बरती ताकि गर्भस्थ शिशु को कोई हानि न पहुँचे। महिला खून पतला करने की दवाओं पर भी थी, गर्भ सुरक्षित रहा।

यह गर्भावस्था के दौरान एंजियोप्लास्टी करने का पहला मामला था।

स्त्री प्रसूति रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. ज्योति जायसवाल स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. रुचि किशोर गुप्ता बताती हैं कि - गर्भावस्था के 37वें हफ्ते में महिला पुनः स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग आई और उसे तुरंत भर्ती किया गया। केस की गंभीरता को देखते हुए गायनी, सर्जरी, एनेस्थीसिया और कार्डियोलॉजी विभाग की संयुक्त टीम बनाई गई। ऑपरेशन के दौरान हमने पाया कि शिशु गर्भाशय में नहीं, बल्कि पेट में विकसित हो रहा था और आंवल कई अंगों से रक्त ले रही थी। टीम ने सुरक्षित रूप से शिशु को बाहर निकाला। साथ ही भारी रक्तस्राव की संभावना को रोकने के लिए सावधानीपूर्वक चिपकी प्लेसेंटा के साथ गर्भाशय को भी निकालना पड़ा।टीम के अथक प्रयासों से शिशु सकुशल पैदा हुआ और माँ भी पूरी तरह स्वस्थ है। महिला की डिलीवरी के बाद उसमें कोई जटिलता ना आए और उसका शिशु भी पूरी तरीके से स्वस्थ रहे इसके लिए हमने लगातार एक महीने तक महिला एवं शिशु को अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद अपने यहां फॉलोअप के लिए बुलाया।

एनईपी-2020 नए छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम - राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से तकनीकी शिक्षा को मिली नई दिशा - तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री खुशवंत साहेब

छत्तीसगढ़ राज्य में तकनीकी शिक्षा को नई ऊँचाइयाँ मिले

रायपुर। राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) के प्रभावी क्रियान्वयन विषय आयोजित कार्यशाला केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि नए छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 के अनुरूप भारत को विकसित एवं समृद्ध राष्ट्र बनाने में नई शिक्षा नीति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ शासन के तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री खुशवंत साहेब ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रहकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक, कौशल आधारित एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से छत्तीसगढ़ राज्य में तकनीकी शिक्षा को नई ऊँचाइयाँ मिलेराष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) के प्रभावी क्रियान्वयन एवं इस विषय पर मार्गदर्शन के उद्देश्य से आज रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला तकनीकी शिक्षा विभाग एवं स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुई।

अनुसंधान और नवाचार को विशेष प्राथमिकता

मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि नई शिक्षा नीति भारत की शिक्षा व्यवस्था को 21 वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तकनीकी शिक्षा संचालनालय के अधीनस्थ तथा स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि एनईपी-2020 से तकनीकी शिक्षा को नई दिशा मिली है, जिसमें कौशल विकास, व्यावसायिक

शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को विशेष प्राथमिकता दी गई है। मल्टीपल एंट्री-एग्जिट सिस्टम, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और इंडस्ट्री लिंक्ड करिकुलम जैसी व्यवस्थाएं शिक्षा को अधिक लचीला और उपयोगी बना रही हैं। श्री वर्मा ने कहा कि कोई भी नीति या योजना तभी सफल होती है जब हम सब मिलकर उस पर कार्य करें। उन्होंने शिक्षकों को परिवर्तन के वास्तविक वाहक बताते हुए कहा कि उनकी सक्रिय भागीदारी से ही नीति के उद्देश्यों की पूर्ति संभव है।

नवाचार, कौशल और भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ना समय की आवश्यकता

मंत्री श्री खुशवंत साहेब ने कहा कि तकनीकी शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा, नवाचार और कौशल विकास को प्रायोगिक स्तर पर सम्मिलित करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने शिक्षकों और संस्थानों से आह्वान किया कि वे विद्यार्थियों को प्रयोग, अनुसंधान और उद्यमिता के लिए प्रेरित करें, ताकि वे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकें। उन्होंने कहा कि एनईपी-2020 के माध्यम से तकनीकी शिक्षा का ढांचा अधिक लचीला, उद्योगोन्मुखी और समकालीन बनाया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को मल्टीपल एंट्री-एग्जिट सिस्टम, एकेडमिक बैंक ऑफक्रेडिट और इंडस्ट्री लिंक्ड करिकुलम जैसी सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा।

कार्यशाला में नीति क्रियान्वयन की दिशा में साझा प्रयास पर बल

कार्यशाला में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्राध्यापकगण, तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी प्रतिभागियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन में साझा समझ, समन्वय और नवाचारपूर्ण दृष्टिकोण आवश्यक है, ताकि छत्तीसगढ़ राज्य में तकनीकी शिक्षा को नई ऊँचाइयाँ मिल सकें।

राज्य का पहला वन विज्ञान केन्द्र

रायपुर । छत्तीसगढ़ में बस्तर वन मंडल के आसना में राज्य के पहले वन विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जायेगी। राष्ट्रीय कैम्पा मिशन भारत सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति दे दी गई है। राष्ट्रीय कैम्पा की 23वीं क्रियान्वयन समिति की बैठक में पायलट बेसेस पर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़िसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मध्यप्रदेश में एक-एक वन विज्ञान केन्द्र शुरू करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में बस्तर के आसना में वन विज्ञान केन्द्र शुरू होगा। इसके संचालन, प्रशिक्षण और पाठ्यक्रमों के निर्धारण के लिए मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर वृत्त की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति में 8 विषय विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है। वन विज्ञान केन्द्र की सलाहकार समिति में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉ. गिरिश चंदेल सहित जशपुर के राजेश गुप्ता, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर के सह-प्राध्यापक डॉ. संजीवन कुमार, रायपुर के गिरीश कुबेर, राजीव शर्मा, डॉ. एम.एल. नायक, सुबोध मनोहर पांडे और पूणे महाराष्ट्र के डॉ. राहुल मुंगीकर को शामिल किया गया है। सरगुजा वृत्त के मुख्य वनसंरक्षक भी समिति के सदस्य होंगे।

बस्तर के वन मंडलाधिकारी को समिति का सदस्य सचिव मनोनित किया गया है।

क्वांटम युग में कोरिया की चमक- अंशिका कश्यप बनीं प्रदेश की टॉपर, अब करेंगी राष्ट्रीय मंच पर प्रतिनिधित्व

रायपुर। रजत जयंती महोत्सव 2025 के अंतर्गत राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर एवं छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी 2025 का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता विगत दिनों शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रायपुर में संपन्न हुआ।संगोष्ठी का विषय था 'क्वांटम युग का आगाज- संभावनाएं एवं चुनौतियां'। इस प्रतियोगिता में सेजेस महलपारा, बैकुंठपुर (जिला कोरिया) की प्रतिभाशाली छात्रा कु. अंशिका कश्यप ने अपने उत्कृष्ट प्रस्तुतीकरण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसे श्नई वैज्ञानिक-तकनीकी क्रांतिश् कहा जाता है, क्योंकि इसमें कंप्यूटिंग, संचार व सेंसरिंग जैसी प्रणालियां क्वांटम कणों के असामान्य व्यवहार का लाभ उठाकर काम करती हैं। इसे इस तरह से समझ जा सकता है, सिक्के को उछालने पर गिरते ही वह या तो हेड होगा या टेल, लेकिन हवा में घूमते समय वह दोनों स्थितियों में 'एक साथ' रहता है, इसी तरह क्वांटम कण भी एक ही समय में बहुत-सी अवस्थाओं में हो सकते हैं, जिसे सुपरपोज़िशन कहते हैं।अंशिका ने यह उपलब्धि भौतिकी विषय की व्याख्याता श्रीमती शिल्पी सिंह के कुशल मार्गदर्शन में हासिल की है। राज्य स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त करने के साथ ही कु. अंशिका कश्यप को अब राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करने का गौरव प्राप्त होगा। यह उपलब्धि न केवल उनके विद्यालय, बल्कि पूरे कोरिया जिले के लिए गर्व का विषय है।शिक्षाविदों और विज्ञान प्रेमियों ने अंशिका को इस शानदार सफलता के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि कोरिया की प्रतिभाओं की क्षमता और परिश्रम का प्रमाण है।

किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवम्बर से प्रारंभ — राज्य शासन ने की विस्तृत तैयारी

रायपुर। राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन 15 नवम्बर 2025 से प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया है। धान उपार्जन की प्रक्रिया को अधिक कृषक उन्मुख, दक्ष और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा संभागवार जिला स्तरीय अधिकारियों की कार्यशाला सह-प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक नागरिक आपूर्ति निगम के सभाकक्ष में आयोजित की जा रही है। सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, प्रबंध संचालक, विपणन संघ तथा संचालक, खाद्य विभाग के मार्गदर्शन में रायपुर एवं बिलासपुर संभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को 15 अक्टूबर 2025 को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण में जिलों से नोडल अधिकारी के रूप में अपर कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर सम्मिलित हुए, साथ ही जिला विपणन अधिकारी, जिला खाद्य अधिकारी, उप-पंजीयक / सहायक पंजीयक सहकारिता, संग्रहण केंद्र प्रभारी, उपार्जन केंद्र प्रभारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि भी प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थित थे। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से होगी धान उपार्जन की सतत निगरानी उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा धान उपार्जन एवं निराकरण प्रक्रिया में संभावित अनियमितताओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से विपणन संघ मुख्यालय स्तर पर 'इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर' की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसके क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर भी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर स्थापित किये जा रहे हैं। इस संदर्भ में मोबाइल एप के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अलर्ट के निराकरण की प्रक्रिया पर संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस हेतु पर्याप्त मानव संसाधन एवं तकनीकी अधोसंरचना की उपलब्धता के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन जिला अधिकारियों को प्रदान किया गया है, जिसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य किया गया है। किसानों की सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रशिक्षण उपार्जन केंद्रों में धान के उचित रखरखाव एवं किसानों की सुविधाओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु उपार्जन केंद्र प्रभारियों और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। गौरतलब है कि सरकार द्वारा किसानों से एक-एक दाना धान खरीदे जाने की प्रतिबद्धता को पूर्ण करने के लिए समिति एवं जिला स्तर के अधिकारियों की संवेदनशीलता और तत्परता अपेक्षित है।

शिक्षा को मिलेगा नया संबल, सरस्वती सायकल वितरण योजना : शिक्षा को मिलेगा नया संबल

पीएमश्री बी.आर.साव स्कूल में 73 छात्राओं को दी गई सरस्वती साइकिल

साइकिल से शिक्षा की राह बनेगी आसानः केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री साहू

रायपुर। सरस्वती साइकिल योजना के तहत आज जिला मुख्यालय मुंगेली स्थित पीएमश्री बी.आर.साव शासकीय हिंदी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 73 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। समारोह में केंद्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू सहित स्थानीय विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले, जिला पंचायत सीईओ श्री प्रभाकर पाण्डेय, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पांडेय सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन किया

गया।

इस अवसर पर केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री साहू ने कहा कि साइकिल से शिक्षा की राह आसान बनेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का उद्देश्य हर विद्यार्थी तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई कर नाम रोशन करने प्रोत्साहित किया। विधायक श्री मोहले ने भी विद्यार्थियों को पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने प्रेरित किया। इस दौरान गणमान्य नागरिक श्री दीनानाथ केशरवानी, नगर पालिका अध्यक्ष श्री रोहित शुक्ला एवं उपाध्यक्ष श्री जयप्रकाश मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। विद्यालय के प्राचार्य और शिक्षकों की उपस्थिति में साइकिल वितरण से छात्राओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।

किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवम्बर से प्रारंभ — राज्य शासन ने की विस्तृत तैयारी

रायपुर, राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन 15 नवम्बर 2025 से प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया है। धान उपार्जन की प्रक्रिया को अधिक कृषक उन्मुख, दक्ष और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा संभागवार जिला स्तरीय अधिकारियों की कार्यशाला सह-प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक नागरिक आपूर्ति निगम के सभाकक्ष में आयोजित की जा रही है। सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, प्रबंध संचालक, विपणन संघ तथा संचालक, खाद्य विभाग के मार्गदर्शन में रायपुर एवं बिलासपुर संभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को 15 अक्टूबर 2025 को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण में जिलों से नोडल अधिकारी के रूप में अपर कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर सम्मिलित हुए, साथ ही जिला विपणन अधिकारी, जिला खाद्य अधिकारी, उप-पंजीयक / सहायक पंजीयक सहकारिता, संग्रहण केंद्र प्रभारी, उपार्जन केंद्र प्रभारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि भी प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थित थे। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से होगी धान उपार्जन की सतत निगरानी उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा धान उपार्जन एवं निराकरण प्रक्रिया में संभावित अनियमितताओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से विपणन संघ मुख्यालय स्तर पर 'इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर' की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसके क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर भी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर स्थापित किये जा रहे हैं। इस संदर्भ में मोबाइल एप के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अलर्ट के निराकरण की प्रक्रिया पर संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस हेतु पर्याप्त मानव संसाधन एवं तकनीकी अधोसंरचना की उपलब्धता के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन जिला अधिकारियों को प्रदान किया गया है, जिसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य किया गया है।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा अस्मा पब्लिशर्स इण्डिया प्राईवेट लि.,जयस्तंभ चौक, रायपुर से मुद्रित कर तथा 5/756 रामसागरपारा, सिंधी स्कूल के पीछे, स्टेशनरी हाऊस, रायपुर 492001 (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक प्रेमेन्द्र अग्रवाल ।
www.lokshakti.in, lokshaktidaily@gmail.com, twitter.com/lokshaktidaily, facebook.com/lokshaktidaily कार्यकारी संपादक : राजेश अग्रवाल (किसी भी विवाद पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा)